1.00 **P.M.**

#GENERAL DISCUSSION ON

&The Union Budget 2024-25
and
&The Budget of Union Territory of Jammu & Kashmir 2024-25 - *Contd.*

MR. CHAIRMAN: Now, further General Discussion on the Union Budget 2024-25 and the Budget of Union Territory of Jammu & Kashmir 2024-25. On 24th July, 2024, Shrimati Sagarika Ghose concluded her speech while participating in the Discussion. I now call upon Members whose names have been received for participation and discussion. The next speaker is Shri Randeep Singh Surjewala. You have 25 minutes.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला (राजस्थान): शुक्रिया सभापति महोदय। माननीया वित्त मंत्री जी ने बजट के भाषण की शुरुआत तीन शब्दों से की - किसान, गरीब और युवा, तो हमारे सहित पूरे देश को एक उम्मीद जगी, पर चंद मिनटों बाद ही पता चला कि यह बजट तो कुर्सी बचाओ, सहयोगी दल पटाओ और हार का बदला लेते जाओ बजट है। सभापति जी, क्या इस सरकार को देश के अन्नदाता किसान की कराहट, गरीब की लाचारी और युवा की बेरोजगारी की चिल्लाहट सुनाई भी देती है?

(**उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए।)*

सवाल यह भी है कि क्या भारत मां के बच्चों का दर्द व उसकी सिसकियों की गूंज सत्ता के गलियारों में अब बेरुखी का सबब बन गई है? क्या जात और धर्म के विभाजन में फंसे, सत्ता में बैठे हुक्मरान इतने * कि उन्हें अब अन्नदाता किसान, गरीब और युवा भी जाति नजर आते हैं?

महोदय, मैं आपका ध्यान बजट के पैरा 14 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें साफ लिखा है कि हम तीन जातियों की बात करेंगे - किसान, महिला और युवा। उपसभापति जी, 75 साल में पहली बार सत्ताधारी सरकार किसान, नौजवान, युवा और महिलाओं को भी जाति और धर्म की वर्ण व्यवस्था से देखने लगी। ...(**व्यवधान**)...

Further discussion continued from 24.07.2024.

& Discussed together.

* Expunged as ordered by the Chair.

श्री उपसभापति: प्लीज़, बैठकर बात न करें। ...(**व्यवधान**)... निषाद जी, बैठकर बात न करें। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़, बैठकर बात न करें। कोई और बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। ...(**व्यवधान**)... सुरजेवाला जी, आप बोलें।

SHRI RANDEEP SINGH SURJEWALA: Please pause my time. ...(*Interruptions*)... If they disturb, please pause my time. ...(*Interruptions*)... मैं माननीया वित्त मंत्री जी को केवल यही कहूंगा कि

"किसी गरीब दुपट्टे का कर्ज है उस पर,
तुम्हारे पास जो रेशम की शॉल है निर्मला जी।"

आइए, जानते हैं, इस बजट में वही तीन शब्द जो इस्तेमाल किए गए हैं - किसान, युवा और गरीब के लिए क्या है। उपसभापति जी, यह बजट खेत, खेती और खेतिहर विरोधी है। इस सरकार ने 10 साल में देश के 72 करोड़ अन्नदाता किसानों, मजदूरों की पीठ में लाठी और पेट में लात मारी है। शरीर के घाव तो मिट गए, पर 72 करोड़ अन्नदाता किसानों की आत्मा के घाव आज भी ज्यों के त्यों हैं। पिछले 10 सालों में कभी सीने पर गोली मारकर या जीप से रौंदकर किसानों का जीवन छीना। कभी 3 काले कानूनों के खिलाफ न्याय मांगते लाखों किसानों के रास्ते में कील, नश्तर और पत्थर बिछा दिए। कभी अन्नदाता किसान को आतंकी, उग्रवादी, मवाली, गुंडा बता हम करोड़ों मेहनतकशों के आत्मसम्मान पर हमला कर डाला और जब उसी अन्नदाता ने 400 पार को 240 पर लाकर खड़ा कर दिया है, तो आज उसकी बजट के माध्यम से आजीविका छीन रहे हैं। लगता है कि जो किसानों और मजदूरों ने सबक सिखाया, वह अब बजट के माध्यम से खेत और खलिहान से बदले के रूप में बदल गया है। इसका सबूत है और उस सबूत को मैं इस पटल पर रखना चाहूंगा। प्रधान मंत्री जी ने देश के अन्नदाता से दो वायदे किए थे।

[**उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी**) *पीठासीन हुए।*]

पहला वायदा था कि किसान को लागत पर 50 प्रतिशत मुनाफा मिलेगा। यानी इनपुट कॉस्ट, फैमिली लेबर, जमीन का किराया और उपकरणों की कीमत पर 50 प्रतिशत मुनाफा मिलेगा, यही एमएसपी होगी। प्रधान मंत्री ने दूसरा वादा किया था कि साल 2022 तक देश में किसान की आय दोगुनी कर दी जाएगी। सवाल यह है कि 2024-25 का यह बजट और सरकार क्या इस पैमाने पर खरी उतरी है? हल बड़ा सीधा था। पहला हल था, या तो सरकार MSP बढ़ाती, फसल की खरीद करती, किसान की आय दोगुनी हो जाती; या फिर सरकार प्रति एकड़ productivity बढ़ाती, एक एकड़ या एक हेक्टेयर में दोगुनी फसल होनी शुरू हो जाती, तो किसान की आय दोगुनी हो जाती। पर क्या यह हो पाया, सवाल यह है? वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के पैराग्राफ 4 में कहा, and I would like to quote her. She said, "अन्नदाता के लिए हमने एक महीने पहले सभी मुख्य फसलों के लिए उच्चतर न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करके लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मार्जिन देने का वादा पूरा किया।" इससे बड़ा असत्य

कोई हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा असत्य कोई हो नहीं सकता। कड़वी सच्चाई यह है कि किसान को लागत जमा 50 प्रतिशत मुनाफा के बराबर MSP नहीं दिया जाता। कड़वी सच्चाई यह भी है कि किसान को घोषित MSP पर फसल खरीदी ही नहीं जाती और कड़वी सच्चाई यह भी है कि हर किसान पर देश में 74 हजार रुपए कर्ज है, परंतु किसान की कर्ज माफी का एक शब्द भी इस बजट में नजर नहीं आता। अब वित्त मंत्री की इन लाइनों के असत्य को मैं आपके समक्ष सबूत समेत साबित करूँगा। उन्होंने कहा कि किसान को लागत पर 50 प्रतिशत मुनाफा दिया, पर खरीफ 2024-25 की लागत प्लस 50 प्रतिशत मुनाफे पर MSP निर्धारित ही नहीं किया। यह मैं नहीं कह रहा, मैं CACP की रिपोर्ट authenticate करने के लिए साथ लेकर आया हूँ, ताकि आप चाहें, तो मैं उसे पटल पर रख दूँ। CACP, यानी देश के कृषि मूल्य निर्धारण आयोग की जो रिपोर्ट है, उसके मुताबिक खरीफ का MSP C2+50 परसेंट नहीं है। अब मैं आपको एक-एक फसल के बारे में बताऊँगा। खरीफ फसल, 2024-25 में धान का C2+50 परसेंट 3,012 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए, मोदी सरकार ने दिया 2,300 रुपए प्रति क्विंटल; यानी 700 रुपए कम। CACP के मुताबिक ज्वार का C2+50 परसेंट होना चाहिए 4,437 रुपए प्रति क्विंटल, सरकार ने दिया 3,371 रुपए प्रति क्विंटल। बाजरे का C2+50 परसेंट होना चाहिए 2,904 रुपए प्रति क्विंटल, आप तो इसे खुद भी लगाते हैं, सरकार ने MSP दिया 2,625 रुपए प्रति क्विंटल। मक्के का C2+50 परसेंट होना चाहिए 2,794 रुपए प्रति क्विंटल, सरकार ने MSP दिया 2,225 रुपए प्रति क्विंटल। CACP रिपोर्ट के मुताबिक रागी का C2+50 परसेंट है 5,197 रुपए प्रति क्विंटल, सरकार ने घोषित किया 4,290 रुपए प्रति क्विंटल। तूर यानी अरहर का C2+50 परसेंट है 9,756 रुपए प्रति क्विंटल, सरकार ने दिया 7,550 रुपए प्रति क्विंटल, यानी दो हजार रुपए कम। मूँग का C2+50 परसेंट है 10,956 रुपए प्रति क्विंटल, सरकार ने दिया 8,682 रुपए प्रति क्विंटल, यानी ढाई हजार रुपए कम। उड़द का C2+50 परसेंट है 9,744 रुपए प्रति क्विंटल, सरकार ने दिया 7,400 रुपए प्रति क्विंटल, यानी दो हजार रुपए प्रति क्विंटल कम। मूँगफली का C2+50 परसेंट है 8,496 रुपए प्रति क्विंटल, सरकार ने MSP दिया 6,783, यानी फिर दो हजार रुपए कम। सोयाबीन का C2+50 परसेंट है 6,436 रुपए प्रति क्विंटल, सरकार ने दिया 4,892 रुपए। मैं पूछता हूँ कि क्या खरीफ 2024-25 में एक ऐसी फसल है, जिसके बारे में वित्त मंत्री ने बजट में कहा कि हमने लागत पर 50 प्रतिशत मुनाफा दे दिया? यह वह रिपोर्ट है, यह आपकी 2024-25 की रिपोर्ट है। C2+50 परसेंट एक फसल का भी नहीं दिया। यानी वित्त मंत्री ने सदन के पटल पर सरेआम बजट में असत्य बोला।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : आप 'असत्य' बोलिए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : मैं 'असत्य' बोलता हूँ, मैं correct करता हूँ। माननीय वाइस चेयरमैन सर, यही नहीं, ये लोग MSP तो घोषित करते हैं, परन्तु MSP पर फसल ही नहीं खरीदते। बीजेपी सरकार में - यह भी मैं अभी साबित करूँगा। ...(**व्यवधान**)... अभी देखिए। ...(**व्यवधान**)... अभी देखिए। ...(**व्यवधान**)... मंत्री जी, जब आपको समय मिलेगा, तब आप बजट के जवाब में बताइएगा। ...(**व्यवधान**)... बीजेपी सरकार में, मोदी सरकार में MSP अब Maximum Suffering for Farmers बन गया है। यह Minimum Support Price नहीं रहा,

क्योंकि MSP के मायने ही नहीं बचे। ये MSP की घोषणा तो करते हैं, परन्तु MSP पर फसल नहीं खरीदते। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, ये 2022-23 के आंकड़े अब कृषि मंत्री जी के कृषि मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद हैं। मैं केवल वह लेकर आया हूँ और मैं आपकी अनुमति से उन्हें सदन के पटल पर रखूँगा।

इनके आंकड़ों के मुताबिक 2022-23 में गेहूँ का उत्पादन 1,068 लाख टन हुआ। उन्हीं के मुताबिक, उन्होंने जो आंकड़े अपलोड किए हैं, सरकार ने 187.92 लाख टन खरीदा। यानी आपने 100 परसेंट उत्पादन के मुकाबले में 18 परसेंट गेहूँ MSP पर खरीदी। * तिलहन - आपके आंकड़ों के मुताबिक, जो कि अभी 2022-23 के ही अपलोड हुए हैं, देश में सोयाबीन, सूरजमुखी, सरसों, मूँगफली, तिल का उत्पादन 377 लाख टन हुआ। आपने कितना खरीदा - MSP पर 48,000 टन। यानी 0.13 परसेंट MSP पर खरीदा। दालें - आपके मुताबिक इनका उत्पादन 276.90 लाख टन हुआ। आपने कितना खरीदा - 1,20,000 टन, यानी 0.43 परसेंट। MSP पर 99.5 परसेंट खरीदा ही नहीं। ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का, जो गुजरात में भी होता है, उनका उत्पादन 491.70 लाख टन हुआ और खरीदा 1.28 लाख टन। ...(**व्यवधान**)... सर, आप हमें तो बोलते हैं कि बैठे-बैठे रिमार्क करते हैं। वहाँ से मिनिस्टर कर रहे हैं, आप उन्हें क्यों नहीं बोलते? ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**) : आप बैठे-बैठे बात नहीं करें। माननीय सदस्य, आप बोलें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर, ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का का उत्पादन 491.70 लाख टन हुआ। इन्होंने कितना खरीदा - 1,28,000 टन, यानी 0.26 परसेंट। धान 1,302 लाख टन पैदा हुआ, लेकिन 651 लाख टन खरीदा, यानी 50 परसेंट। यह चार्ट है, इसका मतलब यह है कि धान की फसल, जो 50 परसेंट खरीदी, अगर उसे छोड़ दूँ, तो गेहूँ, सोयाबीन, सूरजमुखी, सरसों, मूंगफली, तिल, दाल, ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का में एक भी ऐसी फसल नहीं है, जो इन्होंने लगभग 1 परसेंट, 17 परसेंट से ज्यादा MSP पर खरीदी हो। तो उस MSP के मायने ही क्या, जो इस देश के अन्नदाता किसानों को मिलेगा ही नहीं?

सर, यह तो एक बात हुई। मैं आपके समक्ष एक और बड़ा खुलासा करूँगा। ये बजट के अंदर किसान की, गरीब की, अन्नदाता की बड़ी-बड़ी स्कीमें बनाते हैं, उनका नाम लेते हैं, परन्तु उन स्कीम्स का पैसा कभी खर्च नहीं करते। मैंने पिछले 10 सालों के बजट की 6 स्कीम्स का अध्ययन किया, जो कृषि की सबसे बड़ी स्कीम्स हैं। आप यह सुनकर चौंक जाएँगे कि 3 लाख करोड़ रुपए उन 6 स्कीम्स पर इन्होंने खर्च ही नहीं किये। 3 लाख करोड़ रुपए -* मैं एक-एक स्कीम का डेटा लेकर आया हूँ। अगर आप कहेंगे, तो मैं ऑथेंटिकेट कर दूँगा। मैं आपके सारे कागजात लाया हूँ। पीएम किसान योजना - जो आप 2019-20 के अंदर लेकर आए, उसमें 2019 से 2024 के बीच में बजट में कुल 4,03,000 करोड़ रुपए मंजूर किये। मंत्री जी, आप चेक कीजिएगा। उसमें खर्च कितने किये - 2,34,783 करोड़ रुपए, कितने खर्च नहीं किये - 1,68,217

* Expunged as ordered by the Chair.

* Expunged as ordered by the Chair.

करोड़ रुपए, यानी 48 परसेंट आपने अनाउंस किया, लेकिन फिर अपने पास रख लिया। नंबर दो स्कीम ...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्यः कौन सी योजना? ...(**व्यवधान**)...

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः आप पढ़ लीजिएगा। Interest Subsidy for.. ...(**व्यवधान**)... सर, आप देख लीजिए। ...(**व्यवधान**)... आप मेरा समय pause कीजिए, उन्हें समय दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**) : माननीय सदस्य ...(**व्यवधान**)...

SHRI RANDEEP SINGH SURJEWALA: Sir, you have to pause my time. ...*(Interruptions)*... Sir, I will yield to him but you have to pause my time.

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**) : आप बोलिए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः सर, Interest Subsidy for Short-term Credit to Farmers - इन्होंने 2022-23 में इसका नाम चेंज करके Modified Interest Subvention Scheme रख दिया। यह 2016 में शुरू हुई। 2016 से 24 के बीच का बजट 1,68,743 करोड़ है। इसमें 1,11,423 करोड़ रुपए दिये गए। जितना पैसा खर्च नहीं किया गया, वह अपने पास रख लिया, वो 57,320 करोड़ रुपए है, यानी 34 परसेंट। *

तीसरा, 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना', जिसमें पाँच स्कीम्स सब्सूम कर दी गईं, इन्होंने 2015 से 2024 के बीच बजट में इसके लिए 54,543 करोड़ रुपए की बड़ी घोषणा की, लेकिन खर्च कितना हुआ? खर्च केवल 27,385 करोड़ रुपए हुआ। इस प्रकार से 27,158 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए गए, यानी 10 साल से 50 परसेंट खर्च ही नहीं किया गया। *...(**व्यवधान**)... सर, बैठे-बैठे the Minister cannot comment. I will yield. Let him speak, no problem.

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**) **:** कृपया आप बोलिए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के लिए 2014 से 2022 के बीच में 19,478 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन खर्च केवल 14,108 करोड़ रुपए किए गए। इस तरह से 5,370 करोड़ रुपए रख लिए गए। 'पीएम फसल बीमा योजना' के लिए 2014-2024 के बीच में 1,22,050 करोड़ रुपए का बजट दिया गया, लेकिन केवल 88,635 करोड़ रुपए दिए गए। इस प्रकार आप 3,415 करोड़ रुपए, यानी 28 परसेंट 'पीएम फसल बीमा योजना' के भी खा गए। आपके ऊपर * है।...(**व्यवधान**)...

---

* Expunged as ordered by the Chair.

SHRI RANDEEP SINGH SURJEWALA: Sir, please pause my time. ...*(Interruptions)*... सर, मेरा टाइम पॉज़ कीजिए।...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): कृपया आप लोग बैठिए।...(**व्यवधान**)... माननीय सदस्य, कृपया आप बैठिए।...(**व्यवधान**)... आप बीच में डिस्टर्ब न करें।...(**व्यवधान**)... कृपया आप बोलें। यह * शब्द ठीक नहीं है, इसलिए इसको निकाल दिया जाए।...(**व्यवधान**)... कृपया आप बोलिए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: सर, ये खेती की छः स्कीम्स के 2,98,178 करोड़ रुपए, यानी 3 लाख करोड़ रुपए खा गए, इन्होंने दिए नहीं।...(**व्यवधान**)... सर, मेरा टाइम पॉज़ कीजिए।...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): कृपया आप बैठिए।...(**व्यवधान**)... आप विराजिए, बैठिए।...(**व्यवधान**)... आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए....

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: सर, मैं अगले विषय पर चला जाता हूँ, क्योंकि इससे इनको ट्रबल हो रही है। कोई नहीं, मैं इस विषय को छोड़ देता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): आप एकदम से गाँव की भाषा की तरफ चले जाते हैं, आप शहर की भाषा पर आइए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: सर, ठीक है, मैं शहर की भाषा बोलता हूँ, जैसा कि आपका हुक्म है।

सर, मैं जो अगली स्कीम आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, वह 'पीएम किसान सम्मान निधि' है, जो कि इस बजट में भी है। आज देश के 35 प्रतिशत से अधिक किसान 'पीएम किसान सम्मान निधि' से वंचित हैं। आपकी गवर्नमेंट ने 2015-16 में लास्ट एग्रीकल्चर सेंसस किया, उसके बाद कोई एग्रीकल्चर सेंसस नहीं किया। आपके मुताबिक, उस एग्रीकल्चर सेंसस के अनुसार, जो 2018 में आया था, देश में 14 करोड़, 64 लाख किसान हैं। जब आपने 'पीएम किसान सम्मान निधि' शामिल की, तो आपने कहा कि हम 11 करोड़ किसानों को यह देंगे, यानी आपने पहले दिन ही 3 करोड़, 64 लाख किसान, अन्नदाताओं को उससे बाहर कर दिया। कोई बात नहीं, लेकिन 2021-22 में 'पीएम किसान सम्मान निधि' की जो किस्त दी गई, वह 10 करोड़, 79 लाख किसानों को दी गई। अब 18 जून, 2024 को, इस सरकार के गठन के बाद 17वीं किस्त सिर्फ 9 करोड़, 26 लाख किसानों को दी गई, यानी 1 करोड़, 53 लाख किसान और गायब कर दिए गए। इस प्रकार से 3 करोड़, 64 लाख और 1 करोड़, 53 लाख, यानी कुल मिलाकर 5 करोड़, 17 लाख किसान आज 'पीएम किसान सम्मान निधि' से महरूम हैं। 9 करोड़, 26 लाख किसानों को 6 हजार रुपए

* Expunged as ordered by the Chair.

मिलते हैं और 5 करोड़, 17 लाख किसान इससे महरूम हैं। इसका जवाब वित्त मंत्री जी देंगे - यह मुझे विश्वास है।...(**व्यवधान**)...

श्री नीरज शेखर(**उत्तर प्रदेश**)**:** 2014 से पहले कितने किसानों को 'किसान सम्मान निधि' दी जाती थी?...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**) **:** कृपया बैठे-बैठे कमेंट न करें।...(**व्यवधान**)...

SHRI RANDEEP SINGH SURJEWALA: You have to pause my time, Sir. Or you have to control the Member, Sir. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**)**:** कृपया आप बैठिए। कृपया आप बोलिए।...(**व्यवधान**)...

श्री नीरज शेखर: यूपीए की सरकार में कितना दिया जाता था? ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**)**:** नीरज जी, कृपया आप बैठिए।...(**व्यवधान**)...

श्री नीरज शेखर : सर, इनसे बोलिए कि ये बताएँ। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**): यह आप बाद में बता दीजिए, आपको अवसर मिलेगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: सर, सच्चाई कड़वी होती है। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**)**:** आप कृपया बैठ जाएँ। ...(**व्यवधान**)... माननीय सदस्य, आप बैठ जाएँ। ...(**व्यवधान**)...

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: सर, सच्चाई कड़वी होती है, उससे पेट में दर्द होता है। जो किसान विरोधी लोग हैं, उनको जरूर दर्द होता है। मैं अपने साथी को कुछ कह ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों उनको तकलीफ है! ...(**व्यवधान**)... मैंने तो आपको कुछ कहा ही नहीं! ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**): कृपया आप बोलते रहिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: सर, इस बजट में पीएम किसान निधि का पैसा 8,000 करोड़ और काट दिया गया है। 2022-23 में किसान सम्मान निधि का पैसा 68,000 करोड़ था, जो 2023-24 और 2024-25 में 60,000 करोड़ रह गया। इसका मतलब, 5 करोड़ 17 लाख की संख्या जो कम की गई है, तो उनकी संख्या और कम करनी है।

सर, मैं आपके संज्ञान में एक और बात लाऊँगा। ये 6,000 रुपये देने पर बड़ा ढोल पीटते हैं। ये 6,000 रुपये देते हैं और 70,000 रुपये प्रति हेक्टेयर किसान की जेब से निकालते हैं। मैं सबूत के साथ इसको अभी पटल पर रखूँगा। ...(**व्यवधान**)... सर, एक हेक्टेयर में 2.47 या ढाई एकड़ जमीन होती है। इस देश में औसत किसान के पास 1.21 हेक्टेयर है, यानी लगभग 3 एकड़ जमीन है। सरकार द्वारा जो 10 साल में इनपुट कॉस्ट बढ़ाई गई है, खेती पर जो टैक्स लगाया गया है, उसका अतिरिक्त बोझ 23,263 रुपये सालाना है। अगर आप उसको 3 एकड़ से गुणा करें, तो वह 70,000 रुपये बनते हैं। यह कैसे है, यह मैं आपके समक्ष रखूँगा। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो डीजल का रेट 56 रुपये लीटर था। आज जाकर चेक कीजिए, डीजल का रेट 87.62 रुपये लीटर है। यानी , 31.62 रुपये लीटर बढ़ गया। सर, आप भी खुद एक किसान हैं। खास तौर से उत्तर भारत में एक किसान लगभग 250 लीटर प्रति एकड़ डीजल इस्तेमाल करता है। अगर वह इस पर 250 लीटर डीजल इस्तेमाल करता है और इसकी 31.62 रुपये कीमत बढ़ी, तो इसकी कुल कीमत 7,905 रुपये बढ़ गई।

अब खाद पर आ जाइए। जो किसान खाद इस्तेमाल करता है, वह प्रति एकड़ दो बैग, दो कट्टे डीएपी जरूर इस्तेमाल करता है। 2014 में जब यूपीए की सरकार थी, तो डीएपी का रेट 1,150 रुपये था। आप भी आज खरीदते हैं , मैं भी खरीदता हूँ और मित्र लोग भी खरीदते होंगे, आज उसका रेट 1,350 रुपये हो गया। यानी, प्रति बैग के दाम में 200 रुपये का इजाफा हुआ और दो बैग पर 400 रुपये बढ़ गये। हम यूरिया चार बैग एक सीजन में और चार बैग दूसरे सीजन में डालते हैं, तो एक एकड़ में हम आठ बैग यूरिया इस्तेमाल करते हैं। उसका रेट तो 271 ही रहा, पर यह पहली सरकार है, जिसने * 50 किलो का कट्टा 45 किलो का हो गया। अगर 8 बैग इस्तेमाल किए और प्रत्येक बैग से 5 किलो निकल गया ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**): माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

SHRI RANDEEP SINGH SURJEWALA: Sir, you have to pause my time. ...(**व्यवधान**)... Sir, you have to pause my time. Let the hon. Minister speak.

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**): मंत्री महोदय।

श्रम और रोजगार मंत्री; **तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** (**डा. मनसुख मांडविया**) : सर, अभी इन्होंने कहा कि * ऐसा शब्द प्रयोग करके सदन और देश को गुमराह करना उचित नहीं है। आप अपनी बात अवश्य रखें, लेकिन बात में विवेक होना चाहिए। आप आक्षेप-प्रत्याक्षेप कर रहे हैं और बाद में हमारी ओर से कोई सदस्य कुछ कहे तो कहते हैं कि हमें डिस्टर्ब करते हैं। यह उचित नहीं है। आप अपनी बात अवश्य रखें, लेकिन तथ्य के आधार पर रखें और सदन और देश को गुमराह

* Expunged as ordered by the Chair.

न करें। * इसका मतलब क्या है? माननीय वाइस चेयरमैन सर, यह सरकार है, जिसमें हमने 10 साल में फर्टिलाईजर का एक भी रुपया प्राइस नहीं बढ़ाया और कभी कमी नहीं होने दी। हमने पाँच किलो कम इसलिए किया, ताकि वे केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम करें। ...(**व्यवधान**)...

श्री शक्तिसिंह गोहिल (**गुजरात**): सर, ये बीच में कैसे बोल रहे हैं? ...(**व्यवधान**)... जब हमारे मेम्बर बोल रहे हैं, तो ये बीच में टोका-टोकी कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**): शक्तिसिंह जी, आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... देखिए, माननीय सदस्य ने यील्ड किया, वे बैठ गए, इसलिए मैंने मंत्री जी को अलाऊ किया। इतना तो मैं जानता ही हूँ! ...(**व्यवधान**)...

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: सर, बहुत शुक्रिया। रेट तो नहीं बढ़ाया पर खाद कम कर दी, तो रेट ही बढ़ गया। ...(**व्यवधान**)... 50 किलो का 45 किलो हो गया। ...(**व्यवधान**)...

श्री नीरज शेखर: सर, ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**): आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

SHRI RANDEEP SINGH SURJEWALA: Sir, he cannot have a running commentary. I take strong objection to it. I take a very strong objection to it. Sir, you have to either reduce this time or pause my time. He can't have a running commentary. Sir, I am yielding. You let him speak for half an hour.

डा. मनसुख मांडविया: सर, यह सदन में जो मन में आ रहा है, वह बोल रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि उनका बोलने का समय निकल रहा है। महोदय, जो गवर्नमेंट की ज़िम्मेवारी है, हम उसे करेंगे। ...(**व्यवधान**)...

श्री शक्तिसिंह गोहिल: सर, इनको जवाब का समय मिलता है। जब जवाब का समय मिले, तब जवाब दे दें। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**): माननीय सदस्य, यदि कोई माननीय मंत्री महोदय बीच में कुछ कहना चाहते हैं और बोलने वाला सदस्य यील्ड करता है और गलत तथ्य हो, तो उसका अवसर दिया जाता है। ...(**व्यवधान**)...

श्री शक्तिसिंह गोहिल: सर, एक बार, दो बार या बार-बार दिया जाता है!

---

* Expunged as ordered by the Chair.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): माननीय सदस्य, आप बोलें। ...(**व्यवधान**)... सुरजेवाला जी आप बोलें ...(**व्यवधान**)... उन्होंने स्पीच समाप्त नहीं की है, वे अभी बोल रहे हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: सर, इन्होंने मुझे 17 बार interrupt किया है, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मेरा extra समय देंगे। ये मुझे 17 बार interrupt कर चुके हैं, मैं गिन रहा हूं। इसलिए 108 रुपये इसलिए बढ़ गए, क्योंकि 5 किलो खाद कम हो गई। महोदय, पोटाश की जो खाद है, किसान वह कम से कम साल में दो कट्टे डालेगा। वर्ष 2014 में 800 रूपये कीमत थी, जो आज 1,525 रुपये है, 725 रुपये बढ़ा दिए तो साढ़े चौदह सौ रुपये वे बढ़ गए। हम एक एकड़ में दो किलो NPK खाद भी डालते हैं, वर्ष 2014 में उसकी कीमत 750 रुपये थी, आज उसकी कीमत साढ़े तेरह सौ रुपये है, इस हिसाब से साढ़े बारह सौ रुपये उसके बढ़ गए, तो केवल खाद के 3,158 रुपये अतिरिक्त बढ़ गए। सर, बीज की बात करें तो वर्ष 2024 में गेहूं का 2967 बीज आप भी लगाते हैं, मैं भी लगाता हूं और सब किसान लगाते हैं, वह 31 रुपये था, अब 41 रुपये में है, उसके अंदर 400 रुपये बढ़ गए। धान में PR 1121 का जो बीज है, उसमें 10 साल के अंदर 600 रुपये बढ़ गए। कीटनाशक दवाई, गेहूं के herbicide में 1,600 रुपये अतिरिक्त बढ़ गए और धान में जो 4 स्प्रे करते हैं, उसमें 5,000 रुपये बढ़ गए, ये मिल कर 6,600 रुपये हो गए। यह कुल मिलाकर प्रति एकड़ 23,263 यानी 3 एकड़ से अगर मैं औसतन गुणा करूं तो 70 हज़ार रुपये टैक्स लगा कर निकाल लिए और 6 हज़ार रुपये देकर बोलते हैं कि ताली पीटो। यह बड़ा अजीब सिस्टम है।

सर, सरकार के कृषि मंत्रालय ने भी विरोध किया कि गब्बर सिंह टैक्स खेती पर मत लगाओ। यह मैं नहीं कह रहा, मैं आपको स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट, जहां कृषि मंत्रालय ने जवाब दिया, वह पढ़ कर बता रहा हूं। उनकी स्टैंडिंग कमिटी की जो रिपोर्ट है, मैं 69th Report पढ़ रहा हूं उसमें कृषि मंत्रालय ने कहा है and I quote Para 1.18, "In its Action Taken Reply, the Ministry has stated that GST rate slabs are decided by the GST Council. The Ministry of Agriculture and Farmer Welfare since 2017 is continuously pursuing reduction/rationalization in the GST rates for agricultural machines and equipment including tractor, power tillers and combine harvesters." यह सरकार तो अपने कृषि मंत्रालय की बात नहीं सुन रही, देश के किसान की बात कहां से सुनेगी ...(**व्यवधान**)... Again, he is interrupting. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : माननीय सदस्य, आप विराजिए।

SHRI RANDEEP SINGH SURJEWALA: Sir, you have to pause my time. ...*(Interruptions)*... This is the 19th interruption now.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): माननीय सदस्य, थोड़ा मेरा difference है। मेरा 12/12 है, आपका 19/12 है। आप बोलिए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः सर, आप मेरे 12 मिनट बढ़ा दीजिए। मैं आपकी बात मानूंगा, आप बड़े हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): माननीय सदस्य, आप बोलिए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः सर, एक कमाल की बात यह है कि इस देश में अगर कच्चा हीरा है, उस पर जीएसटी है 0.5 प्रतिशत। पॉलिश्ड हीरा है, तो उस पर जीएसटी डेढ़ प्रतिशत है, पर मेरी खाद पर जीएसटी 5 प्रतिशत है, मेरी pesticide पर, कीटनाशक दवाई पर 18 प्रतिशत जीएसटी है, ट्रैक्टर पर 12 परसेंट है। किसी सरकार के लिए इससे ज्यादा * की बात क्या हो सकती है कि हीरे पर जीएसटी आधा और डेढ़ परसेंट है और किसान के ट्रैक्टर पर 12 परसेंट है, कीटनाशक दवाई पर 18 परसेंट है, यह इस सरकार की असलियत है।

सर, एक तरफ एमएसपी नहीं बढ़ा, न एमएसपी पर खरीद हुई, जैसा मैंने साबित किया। दूसरी तरफ प्रति एकड़ productivity भी कम हो गई है। ...(**व्यवधान**)... Sir, you have to pause my time or you have to name the Member.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): माननीय सदस्य, आप बोलिए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः सर, 10 साल में पैदावार की combined growth rate बस 2 प्रतिशत रह गई है। यह किसान की हालत है। चावल की growth 1.7 प्रतिशत, गेहूं की growth 1.7 प्रतिशत, सोयाबीन की growth 0.6 प्रतिशत, ऑयल सीड की growth 1.8 प्रतिशत, तुअर दाल की growth 1.9 प्रतिशत है। कैसे आय दुगुनी होगी? जब आपकी ग्रोथ रेट ही 1.7 प्रतिशत है और यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि सीएसीपी की जो ताजी रिपोर्ट आई है, अगर ये पढ़ते, तो उन्होंने इसमें लिखा हुआ है। सर, चौकाने वाली बात यह है कि जो ताजा रिपोर्ट है, उसके अंदर यह भी लिख दिया कि agriculture and allied sector की जो ग्रोथ है, वह 2023-24 में मात्र 0.7 प्रतिशत रहेगी। यह देश का Commission for Agricultural Costs and Prices कह रहा है। ऐसे में किसान की आय दुगुनी होने में 100 साल लगेंगे। यह हालत है। नाम बड़े, दर्शन छोटे, असली में इनका यही है।

सर, तिलहन और दलहन के बारे में वित्त मंत्री जी ने पैरा 13 में कहा कि हम इस पर आत्मनिर्भर हो गए हैं, लेकिन वे दो बातें बताना भूल गई हैं। पहली बात यह है कि भारत की जरूरत का 60 प्रतिशत खाने का तेल आज भी हम इम्पोर्ट करते हैं। 2022-23 में इन्होंने 157 लाख टन, यानी 1,67,000 करोड़ का खाने का तेल आयात किया, जो 2021-22 के मुकाबले में डबल था। इस साल 2023-24 में यह नौ महीने में ही 121 लाख टन आयात कर चुके हैं और वित्त मंत्री जी बजट के पैरा 14 में कहती हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं। दाल के बारे में भी उन्होंने कहा कि हम आत्मनिर्भर हैं, पर 2023-24 में अप्रैल और दिसंबर के बीच 28, 40,000 टन दाल का आयात हुआ है। उसमें अधिकतर Adani Wilmar के द्वारा किया गया है। सर, 2022-23 में 17.5 lakh tone था।

---

* Expunged as ordered by the Chair.

दाल का आयात बढ़ रहा है, तेल का आयात बढ़ रहा है और वित्त मंत्री पैरा 14 में कहती हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं। सर, ऐसी 11 schemes हैं...(**व्यवधान**)... मैं यहां ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि आपने मुझे 12 minutes extra दिए हैं। जिनमें इन्होंने पैसा काट लिया।...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**) **:** जितना एक्स्ट्रा समय लेंगे, आपकी पार्टी का ही है।

श्री रणदीप सुरजेवाला: सर, मेरी interruptions का तो एक्स्ट्रा समय देंगे। मैं यह कहना चाहूंगा कि ये जान लें और पहचान लें कि देश का अन्नदाता किसान आपके जुल्मों के आगे झुकेगा नहीं और न्याय के पथ पर रूकेगा भी नहीं। जैसा मेरे लीडर राहुल गांधी और खरगे जी कहते हैं किसानों को दरबारों की दरकार नहीं, अन्नदाता तो महलों पर बैठे हुए मठाधीशों को खेत और खलिहानों की दयोढ़ी पर झुकाता आया है। ...(**समय की घंटी**)... इसलिए किसी ने कहा है कि

"ऊंचे-ऊंचे दरबारों से क्या लेना,
वो बेचारे हैं, बेचारों से क्या लेना,
जो मांगेंगे, तूफानों से मांगेंगे,
सत्ता में मदहोश इन अहंकारी गलियारों से क्या लेना।
अपने संकल्प की सिद्धी से जीतनी है यह जंग हमने,
लकड़ी की तुम्हारी तलवारों से क्या लेना।"

सर, एक पहलू और है, जो गरीब का है। ...(**समय की घंटी**)... मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। पीएम गरीब कल्याण के नाम पर 80 crore लोगों को 13.75 रूपये का आपने झुनझुना पकड़ाया है। उसका सबूत भी मैं लेकर आया हूं। सर, Congress Party और UPA की सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लेकर आई थी। इन्होंने उसका नाम बदलकर पीएम गरीब कल्याण योजना रख दिया।...(**व्यवधान**)... NFSA में पहले से ही, ...(**व्यवधान**)... महोदय, वे मुझे interrupt कर रहे हैं, तो कृपया मेरा time pause कीजिए।...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**) **:** कृपया आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री रणदीप सुरजेवाला: NFSA में पहले से ही हर व्यक्ति को ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**)**:** सुरजेवाला जी को अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

श्री रणदीप सुरजेवाला: NFSA में पहले से ही हर व्यक्ति को पांच किलो अनाज हर महीने देने का प्रावधान है। National Food Security Act में 3 रुपये प्रति किलो की रियायती दर से चावल और 2 रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर गेहूं हम पहले से ही दे रहे थे। आजकल 75 प्रतिशत चावल और 25 प्रतिशत गेहूं देते हैं। 80 crore लोगों को पांच किलो चावल में से 75 प्रतिशत, 60 crore हो गए। 60 crore को अगर पांच किलो चावल 3 रुपये की रियायती दर से दें, तो 900

crore बनते हैं। 20 crore को 2 रुपये की रियायती दर से गेहूं दें, तो 200 crore बनते हैं। कितने बने 80 crore को, 1,100 crore, बाकी हम पहले से दे रहे थे। 1,100 crore, 80 crore को, तो 13.75 रुपये बनते हैं। इसलिए कहते हैं कि गरीब के अधिकार पर भी marketing करना। जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून scheme हमने बनाई, उसमें 3 रुपये और 2 रुपये पर पहले से दिया जा रहा था। ...(**समय की घंटी**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : आप समाप्त कीजिए।

श्री रणदीप सुरजेवालाः आप 13.75 रुपये देते हैं। सर, आपने मुझे कहा था कि मेरी interruptions के 11 minutes मुझे देंगे।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : मैंने उसकी पूर्ति कर दी है।

श्री रणदीप सुरजेवालाः सर, 5 minutes हुए हैं, वह देखिए। आपने पांच मिनट ही दिए हैं। मैं एक छोटा सा पहलू कहना चाहूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री रणदीप सुरजेवालाः सर, आपने ही 10 minutes कहा था।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): मैं नहीं देने वाला हूं। आपकी पार्टी ने आपको समय दिया है। आप समाप्त कीजिए।

SHRI RANDEEP SINGH SURJEWALA: Okay. Sir, give me two minutes, I am winding up.सर, तीसरा पहलू बेरोजगारी का है। आज बेरोजगारी सबसे बड़ी महामारी है। सर, मैं तीन तथ्य रखकर एक मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। सर, वायदा था दो करोड़ रोजगार देने का यानी 10 साल में 20 करोड़ रोजगार देने का, पर इस सरकार का दुर्भाग्य यह है कि यहां प्रधान मंत्री को ही पता नहीं कि कितनों को रोजगार दिए हैं। मैं आपको उसके तीन उदारहण देना चाहता हूं। 5 मई, 2024 को प्रधान मंत्री के पूर्व आर्थिक सलाहकार कहते हैं कि पिछले 8 साल में एक करोड़ नौकरियाँ दीं। 20 मई, 2024 को, मैं एक साक्षात्कार का वीडियो लेकर आया हूं, प्रधान मंत्री जी एनडीटीवी को साक्षात्कार में कहते हैं कि 7 साल में 6 करोड़ नौकरियां दीं। उसके 58 दिन बाद प्रधान मंत्री जी 13 जुलाई, 2024 को मुम्बई में कहते हैं कि 3 साल में 8 करोड़ नौकरियां दीं। उसके एक दिन के बाद प्रधान मंत्री जी की केबिनेट के एक मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी कहते हैं कि 10 साल में साढ़े 12 करोड़ नौकरियां दीं। ...(**समय की घंटी**)... सर, मैं जानना चाहता हूं कि कितनी नौकरियां दी हैं?

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): माननीय सदस्य समाप्त करिए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: सर, मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूं, क्योंकि प्रधान मंत्री जी का ...।

उपसभाध्यक्ष: माननीय सदस्य समाप्त करिए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: सर, अगर देश के प्रधान मंत्री जी को ही पता नहीं कि नौकरी कितनी दीं, तो क्या होगा?

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**): माननीय सदस्य समाप्त करिए।

SHRI RANDEEP SINGH SURJEWALA: Sir, I am concluding.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Now, Shri M. Shanmugam.

SHRI M. SHANMUGAM (Tamil Nadu): Yes, Sir.

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**): कृपया आप समाप्त करिए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: लास्ट दो लाइन बोलने दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**): मैंने माननीय सदस्य को बोलने के लिए पुकार लिया है, hon. Shri M. Shanmugam.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: सर, ये एक झुनझुना बजट लेकर आए हैं। यह बजट है बदला लो, कुर्सी बचाओ। 400 के वायदे को 240 पर लाकर छोड़ने की सजा अब प्रांतों को दी जा रही है।

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**): आपका बोलने का समय समाप्त हुआ। माननीय एम. शनमुगम।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला:*

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**): आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। माननीय सदस्य आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है।

---

* Not recorded.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला:*

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): सुरजेवाला जी, आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। आप बैठ जाइए। Now, Shri M. Shanmugam. अंकित नहीं होगा। आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं आएगी।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): यह रिकॉर्ड में नहीं आएगा।

SHRI M. SHANMUGAM: Sir, I will speak in Tamil.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला:*

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): यह रिकॉर्ड में नहीं आएगा। आप बैठ जाइए, धन्यवाद। Now, Shri M. Shanmugam.

SHRI M. SHANMUGAM: Sir, I will speak in Tamil.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Yes.

SHRI M. SHANMUGAM: @"Mr. Vice Chairman Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak on Budget 2024-25. Hon. Finance Minister of India, our dear sister from Tamil Nadu, had presented the Budget for the seventh time. Tamil Nadu has been totally neglected in the budget. It may be because our dear sister is from Tamil Nadu. I am not mentioning this to find fault with her. This Budget had neglected not only Tamil Nadu, but also all the non-BJP ruled states. I would like to quote a *Thirukkural, Kural couplet no.448)* It means, "The king, who is without the guard of men who can rebuke him, will perish, even though there be no one to destroy him."

Sir, So many disasters have happened in so many states. In order to help people on time, the State Governments had spent a lot of money on the basis of exigency. Later, the teams of Union Government visit the site and make recommendations. But the thousands of crores of rupees spent by State Governments during the relief measures of such calamities, have not been provided by the Union Government. It is really regrettable. At the same time, disaster relief fund is allocated to some states even before the occurrence of disaster. Perhaps, the

---

* Not recorded.

@ English translation of the original speech delivered in Tamil.

motto of 'Prevention is better than cure" is followed only for some states. India, being a peninsula, is surrounded by sea on three sides and by mountains on one side. Therefore, due to weather fluctuations, coastal states are severely affected by natural calamities. We would like to demand in this House that hon. Finance Minister should release the due financial assistance considering these factors also.

NITI Aayog had appreciated the performance of Tamil Nadu in its report. They have certified that Tamil Nadu had excelled in urban development and in the functioning of Panchayat Unions. I would like to point out that this development is possible because of the Dravidian model of governance, led by our Commandant Mr. M.K.Stalin, hon. Chief Minister of Tamil Nadu. But, you are very partial towards him, without allocating the financial assistance to Tamil Nadu whenever he requests the Union Government. He requests the amount which is due for Tamil Nadu. But it is not given to the state. This trend is continuously followed for three years. It is our duty to record in this House that you are showing partiality in disbursing the fund due for our state.

In the emerging urbanisation scenario, transport sector occupies a vital place. Metro rail projects are being implemented keeping this objective in mind. The second phase of Chennai Metro rail project has begun only with the share of the State Government of Tamil Nadu. The Centre has not yet contributed its share. Madam, most of the tax receipts are in your hand. The State Government of Tamil Nadu is managing its finances with the fewer available resources that are in states' domain. Is it fair on your part not to provide the financial assistance on time?

An exclusive rail network for eastern coastal region should be brought, similar to the network of Konkan Railways that covers the western coastal region. When Sethu Samudram project was implemented, you criticized that Ram Setu Bridge would be affected. But that bridge is not found till today. The Government has to come forward to lay a bridge between Dhanushkodi and Thalaimanaar to nurture bilateral relationship between India and Sri Lanka.

If one searches the phrase, 'Employment to youth' in this Budget, he would be disappointed. It is mentioned nowhere. Government is interested in filling up the vacancies of only higher officials that is, Group A and Group B officers, Officers of civil services such as IAS, IPS etc. But there are lakhs of vacancies at Group D level which are unfilled. This is evident particularly in the Department of Railways. Movement of trains is severely affected due to lack of sufficient number of employees at lower levels. Accidents happen. Hundreds of people die. But there is no shortage of senior officers who can make enquiries.

Mr. Vice Chairman Sir, please look at the ratio of higher officials to lower level employees, since Independence. Now, the numberof officers have increased, but the number of subordinates have decreased. Earlier, a district comprised of 15 Taluks, administered by one District Collector of the rank of IAS. But, now, a district has only two Taluks and a district collector is in charge of supervising two taluks only. It is really strange to note that subordinate vacancies are filled up on contractual basis. It is ironical that such contractual employment is followed in the Department of Labour also. It is highly regrettable.

Public sector Units have made significant achievements. I would like to mention the significant achievements of BSNL which is one of the largest Public sector Units in India. Its network is spread everywhere in the country similar to the nervous system of human beings. Whether it is about the laying of cables beneath the Andaman seas or carrying them to the peaks of Himalayas, BSNL's presence is there. If one needs telecommunication during floods and disasters, we need the assistance of BSNL. But the Government does not give the benefits to BSNL as it gives to private sector i.e. Government is partial towards BSNL. The private companies nurtured by you have increased their rates, therefore, many customers return to BSNL now. We have come to know that the Government had offered satellite network to TATA company and is utilizing the infrastructure of BSNL to serve this purpose. Earlier, many private airlines are encouraged to compete with Air India. Later, Air India was destroyed and was handed over to TATA. Similar steps are being taken now with regard to BSNL also.

Increment is not given to BSNL employees during the past eight years. Many PSUs are achieving many milestones despite such difficulties. But Hon'ble Prime Minister of India feels proud at their achievements and gets the credit for their achievements without safeguarding their livelihood.

It is not fair to give alternative views instead of giving assurance to implement Old Pension Scheme which is desired by employees. I would like to convey that it is the duty of the Government to implement old Pension scheme and to withdraw New Pension Scheme.

Lakhs of employees under EPF pension scheme have demanded to increase their pension. EPFO does not give proper information about the accounts of employees, their due income and expenditure etc. It was said that the share of corpus fund in family pension scheme of 1972 is merged with pension scheme of 1995. It has not yet been informed about the actual amount, that is the corpus fund. How many people who have benefited from the pension scheme of 1995, had passed away till date? What happened to their Corpus Fund? Employees are not fully aware

of this EPF scheme since its inception in 1952 till 2014. When they migrate from one company to another company, they create new account. They do not know how to receive their dues from the previous company. Hence, lakhs of crores of amount is lying with EPFO as unclaimed amount. EPFO has not informed anyone about this fact till date. Workers had to sweat a lot to save some money. They sincerely deposit their savings in EPFO. But that organization itself functions like a capitalist doing injustice to employees. It is reprehensible that employees are forced to run from pillar to post to receive their dues. Therefore, I request the Department of Finance to examine this matter seriously and to increase the amount of pension due for employees, by taking all these factors into consideration and to give them justice.

Transport Employees of Tamil Nadu had to be paid EPFO dues. The amount is more than Rs.1300 crore. It is not justifiable to drag the settlement of their claims. India Labour conference has to be convened immediately to discuss labour issues. Four anti labour legislations codes that snatch away the rights of labourers have to be withdrawn. Minimum Support price has to be given to farmers, as per the recommendations of M.S. Swaminathan committee. There is no mention about MGNREGA in the Budget, a huge scheme that guarantees 100 days of employment in rural areas. There is no mention of increasing the allocation for this scheme.

Crores of employees are unorganized labourers. This budget does not mention anything about social security schemes for them. In brief, this Budget has not given any benefit to labourers, peasants, small scale entrepreneurs and traders. It is loyal only to their allies. On behalf of my party DMK, we oppose this budget. I would like to conclude my speech by mentioning the demand of our leader that States should be given their rights honestly. Thank you.

श्री राघव चड्ढा (पंजाब) : सर, आम तौर देखा जाता है कि जब भी वित्तीय बजट देश में प्रस्तुत किया जाता है, तो देश के कुछ वर्ग उस बजट से खुश होते हैं और कुछ वर्ग उस बजट से निराश होते हैं, लेकिन इस बार सरकार ने वह अचीव कर लिया, जिसे अचीव करना संभव ही नहीं था। इस सरकार ने इस बजट से देश के लगभग हर वर्ग को निराश किया है। They have managed to displease all sections of our society. In fact, Sir, भारतीय जनता पार्टी के अपने समर्थक भी, अपने वोटर भी इस बजट से बेहद निराश हैं। सर, बजट 2024 में... ...(**व्यवधान**)... सर, मुझे बोलने दीजिए, नहीं तो मैं... ...(**व्यवधान**)... if you wanted me to yield, नहीं तो मैं बैठ जाता हूँ। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**): माननीय सदस्यो... ...(**व्यवधान**)... माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... चड्ढा जी, आप बोलिए। ...(**व्यवधान**)... Please continue.

श्री राघव चड्ढाः सर, पिछले दस सालों में टैक्स लगा-लगाकर सरकार ने देश के आम आदमी का खून चूस लिया है। मान लीजिए, आप दस रुपये कमाते हैं, उसमें से तीन-साढ़े तीन रुपये आप इनकम टैक्स के माध्यम से दे देते हैं, दो-ढाई रुपये जीएसटी चूस लेता है, दो रुपये आपका केपिटल गेन टैक्स लगता है, सेस सरचार्जेज़ एक-डेढ़ रुपये के लग जाते हैं, तो मात्र दस रुपये में से सात-आठ रुपये तो सरकार के खजाने में चले जाते हैं।...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**) : माननीय सदस्यो... ...(**व्यवधान**)...

श्री राघव चड्ढाः आम इंसान को मिलता क्या है, आम आदमी को मिलता क्या है? सरकार जो हमसे इतना टैक्स लेती है, उसके बदले में हमें देती क्या है? सरकार बदले में कौन सी ऐसी अंतरराष्ट्रीय सेवाएं, वर्ल्ड क्लास हेल्थकेयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं देशवासियों को देती हैं, मैं यह भी पूछना चाहता हूँ? आज मुझे यह कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि Sir, we in India, today pay taxes like England to get services like Somalia. ...(व्यवधान)... सर, मैं अपने इस भाषण को दो भाग में बाटूँगा। पहले भाग में मैं सरकार की 2024 के चुनावों में इतनी दुर्दशा क्यों हुई और आज की आर्थिक स्थिति क्या है, इस पर बात करूँगा और दूसरे भाग में सरकार को कुछ सुझाव भी दूँगा। सर, 2019 में भारतीय जनता पार्टी की 303 सीटें थीं। देश की जनता ने उन सीटों पर 18 परसेंट जीएसटी लगाकर, इनको 240 सीटों पर ला खड़ा किया। सर, इसके कई कारण बताए जाते हैं। कोई कहता है कि धर्म का कार्ड नहीं चला, कोई कहता है कि जातीय कारण है, तो कोई कहने लगता है कि टिकट डिस्ट्रिब्यूशन में कमी रही। सर, ये सभी ऊपरी कारण हैं। मैं तीन कारण बताता हूं, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी की यह दुर्दशा हुई। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**) : माननीय सदस्य ...(**व्यवधान**)...

श्री राघव चड्ढाः पहला कारण है इकोनॉमी, दूसरा कारण है इकोनॉमी और तीसरा कारण भी इकोनॉमी है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**) : माननीय सदस्य, प्लीज़ सुनिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री राघव चड्ढा : सर, मैं बैठ जाता हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**)**:** आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)... यह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा नहीं है। यह आम बजट पर चर्चा है। ...(**व्यवधान**)... माननीय राघव चड्ढा जी। ...(**व्यवधान**)... आपस में बात न करें। ...(**व्यवधान**)... माननीय राघव चड्ढा जी, यह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा नहीं है। यह आम बजट पर चर्चा है। ...(**व्यवधान**)... आप बोलिए।

श्री राघव चड्ढाः सर, अगर आपने मेरी पूरी बात सुनी होती, तो शायद इतनी आपत्ति इन लोगों को न होती। सर, मैं यही कहना चाहता हूं कि चुनावी हार के कई कारण बताए जाते हैं, लेकिन मेरे मुताबिक तीन महत्वपूर्ण कारण हैं। ...(**व्यवधान**)... पहला कारण इकोनॉमी, दूसरा कारण इकोनॉमी और तीसरा कारण भी इकोनॉमी है। ...(**व्यवधान**)... मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, चुनावों की बात नहीं कर रहा हूं। ...(**व्यवधान**)... सर, मैं बैठ जाता हूं, इनको चिल्लाने दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी)ः माननीय सदस्य, बैठिए। जब आपका समय आए, तो बता देना कि दिल्ली में कैसे हारे। अभी उनको बोलने दीजिए। ...(**व्यवधान**)... आप बोलिए।

श्री राघव चड्ढाः सर, हार का पहला कारण rural income and inflation है। भारत की 60 प्रतिशत से ज्यादा आबादी गांव में बसती है। लेकिन आज ...(**व्यवधान**)... सर, यह ठीक नहीं है। इनकी तबियत खराब है। ...(**व्यवधान**)... इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ...(**व्यवधान**)... सर, क्या आज इनकी तबियत खराब है? ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी)ः माननीय सदस्य, आप बैठ जाएं। ...(**व्यवधान**)... कृपया बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... कृपया बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... माननीय सदस्य, आप डिस्टर्ब मत करें। इनको बोलने दें। आपको बोलने का अवसर मिलेगा। अभी इनको बोलने दें।

श्री राघव चड्ढाः सर, मैंने ढाई मिनट बोला है, उसमें इन्होंने पांच बार इंटरेप्ट किया है। मैं अपना समय सूद समेत इनसे वसूलूंगा। सर, मैं आगे चलता हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी)ः यह ब्याज की आदत ठीक नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री राघव चड्ढाः सर, आज rising rural inflation, rural unemployment, low crop yield, income inequality, farmer debt, high input cost, low income, no MSP और crop losses के चलते यह आलम है कि rural income growth वित्तीय वर्ष 2023-24 में decadal low पर है। सर, इसी के साथ-साथ किसानों की आय दोगुना करने का वायदा था, स्वामिनाथन कमीशन के अनुसार एमएसपी देने का वायदा था। वे वायदे जब पूरे नहीं हुए, तो आलम यह है कि पिछले 25 महीने लगातार real rural wages decline पर हैं। इसके साथ-साथ UPA के दौरान, कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान farm wages में 8.5 प्रतिशत का इजाफा देखा गया था। एनडीए 1 के दौरान 3 परसेंट और एनडीए 2 के दौरान -0.6 परसेंट का इजाफा देखा गया है, यानी कि rural wages गिरती जा रही हैं। ...(**व्यवधान**)...

सर, मैं इसे साधारण भाषा में समझाता हूं। 2014 में एक दिहाड़ी मजदूर एक दिन की अपनी दिहाड़ी से 3 किलो अरहर की दाल खरीद सकता था, आज वही दिहाड़ी मजदूर वर्ष 2024 में एक दिन की दिहाड़ी से 1.5 किलो अरहर दाल खरीद पा रहा है। यानी महंगाई भी बढ़ रही है और उसकी आमदनी भी घट रही है। सर, इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा यह हुआ कि

इनका वोट शेयर घटा। रूरल एरियाज़ में भाजपा का वोट शेयर 5 प्रतिशत घटा। ...(**व्यवधान**)... इनके खुद के यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर चुनाव हार गए। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : माननीय सदस्य, बैठकर बात नहीं करें।

श्री राघव चड्ढाः 2019 में 398 रूरल सीट्स में से इनको 236 सीट्स मिली थीं और इस बार 398 सीट्स में मात्र 165 सीटें मिली हैं। यानी कि रूरल इंडिया में इनको नकार दिया गया है।

सर, आज देश में जो आर्थिक स्थिति है और वह कारण जिसकी वजह से इनकी चुनावों में यह दशा हुई, वह है फूड इनफ्लेशन। सर, थाली का बजट बिगड़ गया। चाहे आटा हो, दूध हो, चावल हो, दही हो, हर वस्तु पर महंगाई का आलम है, जीएसटी का आलम है और लगातार इस देश में फूड इनफ्लेशन बढ़ता जा रहा है। इस देश में लगभग 9 से 9.5 प्रतिशत के आसपास फूड इनफ्लेशन मंडरा रहा है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि वे commodities, जिनमें हम self-sufficient थे; वे commodities, जिनका हम export किया करते थे, उनमें कैसे महँगाई घुस गई? अगर वे commodities भी महँगी हो गई हैं, तो उसका फायदा किसान को क्यों नहीं मिलता? वह सारा पैसा जा कहाँ रहा है, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है।

सर, 2014 में आटा 21 रुपए प्रति किलो बिका करता था, आज 42 रुपए प्रति किलो हो गया है। वर्ष 2014 में दूध 30 रुपए प्रति लीटर के आसपास बिका करता था, आज 2024 में 70 रुपए प्रति लीटर बिकता है। देसी घी 2014 में 300 रुपए प्रति किलो पर बिका करता था, आज 2024 में 675 रुपए प्रति किलो बिकता है। 2014 में अरहर की दाल 80 रुपए प्रति किलो बिका करती थी, आज 230 रुपए प्रति किलो बिक रही है। और न जाने कितनी वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। अगर महँगाई की यही रफ्तार रही, तो ये लोग जितनी रफ्तार से 303 से 240 पर आए हैं, उससे तेज रफ्तार से 240 से 120 पर आएँगे।

सर, third reason is unemployment, यानी बेरोजगारी। सर, informal sector हो या formal sector हो; unorganized sector हो या organized sector हो; हर जगह unemployment है। CMIE की रिपोर्ट यह बताती है कि इस देश में organized sector की unemployment दर 9.2 परसेंट है। Unorganized sector की तो बात ही भूल जाइए, organized sector की unemployment दर 9.2 परसेंट है। सर, हम लोगों ने अपने देश के human resources को किस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है, उसका आलम देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार के सचिवालय में peon की पोस्ट के लिए 368 नौकरियाँ निकलीं, उनके लिए 23 लाख लोगों ने आवेदन पत्र दिए!

[**उपसभाध्यक्ष (सुश्री कविता पाटीदार**) *पीठासीन हुईं*]

Indian Railways के Group 'D' employees में 63,000 posts निकलीं, उनके लिए 2.5 करोड़ लोगों ने आवेदन पत्र दिए! मैडम, 2.5 करोड़ आस्ट्रेलिया की आबादी से भी ज्यादा है। मैडम, बिहार पुलिस 9,900 constable posts निकालती है, उनके लिए 11 लाख आवेदन पत्र आते हैं! मैडम, सारी चीजें छोड़िए, महाराष्ट्र सचिवालय के कैंटीन में 12 वेटर्स को भर्ती करने के लिए जब

आवेदन पत्र माँगे गए, तो 7 हजार लोगों ने आवेदन पत्र दिए, जिनमें कई post-graduates और graduates भी शामिल थे। मैडम, यह बेरोजगारी का आलम है!

मैडम, चौथा - key sector stagnation. इस देश में जितने key sectors हैं, construction हो, trade हो, जो employment create करते हैं, उनमें stagnation आता जा रहा है और industry का investment, जिसे Gross Fixed Capital Formation कहते हैं, वह लगातार घटती जा रही है। मुझे बताते हुए दुख है कि new private investment वित्तीय वर्ष 2024-25 के पहले क्वार्टर में 25 year low पर आ खड़ा है, यानी आज भारत देश की industries निवेश नहीं कर रही हैं।

मैडम, पाँचवाँ कारण है गिरती हुई per capita income, यानी प्रति व्यक्ति आय। देश के 12 राज्यों में लगातार per capita income घटी। उन 12 में से 9 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का vote share भी घटा।

मैडम, छठा कारण decline in financial savings and rising debt burden on the Indian household, यानी औसतन भारतीय परिवार का कर्ज बढ़ता जा रहा है और उसकी savings घटती जा रही हैं। हम लोग financially fragile होते जा रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने खुद कहा कि savings bank account खातों में से savings गायब होती नजर आ रही हैं। हमारा net financial savings to GDP ratio घट रहा है, household savings घट रही हैं और लगातार savings में decline देखा गया।

मैडम, मैं सिर्फ बुराई नहीं करना चाहता, सुझाव भी देना चाहता हूँ। मैं अपने आने वाले भाषण के भाग में सरकार के लिए 8-10 महत्वपूर्ण सुझाव भी लाया हूँ। मैं देश हित में, देश की अर्थव्यवस्था के हित में सुझाव देना चाहता हूँ। पहला सुझाव, Index Minimum Wages with Inflation, यानी न्यूनतम मजदूरी आय को बढ़ती महँगाई के साथ जोड़िए। मैडम, inflation erodes purchasing power. महँगाई वह दीमक है, जो आपकी purchasing power, आपकी संपत्ति को खा जाती है। इसीलिए आज मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे बेल्जियम जैसे देशों ने automatic indexation of wages लागू किया है, उसी प्रकार हमारे देश में भी minimum wages की automatic indexation होनी चाहिए। यहाँ मैं यह बताना चाहूँगा कि मेरे नेता, अरविंद केजरीवाल जी ने, हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार ने देश में सबसे ज्यादा minimum wages दिल्ली में देने का काम किया।

मैडम, मेरा दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव है - Re-work the Agricultural Pricing Formula. यानी जब किसान खुले बाजार में अपनी फसल बेचने जाता है, तो वहाँ पर एक minimum reserve price होना चाहिए, यानी उस price के नीचे किसान की कमाई नहीं होगी, किसान को उस रेखा के नीचे का दाम नहीं मिलेगा। इससे किसान price volatility से बचेगा, किसान को economic security मिलेगी और production में continuity रहेगी।

मैडम, मेरा तीसरा सुझाव है - Legal Guarantee with MSP in accordance with Swaminathan Commission's Report. स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट की बात सुनते-सुनते कि हम लागू करेंगे, मेरे भी बाल पक गए हैं, लेकिन यह आज तक लागू नहीं हुआ। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि वह उस legal guarantee को देश के किसान को सौंपे।

चौथा और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव - मैं हाथ जोड़ कर विनती करना चाहूँगा - restore indexation on long term capital gain. मैडम, पूरी दुनिया में इंवेस्टर्स को इंवेस्टमेंट्स करने को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिवाइज किया जाता है। इस देश में इंडेक्सेशन हटाकर हम इंवेस्टर क्लास को इंवेस्ट करने के लिए डिस्इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। इंडेक्सेशन हटाना टैक्स लगाना नहीं है, इंवेस्टर्स को पेनलाइज करने जैसा है।

2.00 P.M.

मैडम, मैं बताना चाहता हूँ कि ravages the value of money. Inflation पैसे को खा जाता है। इसीलिए हम cost of acquisition को index करके capital gain tax की calculation करते हैं। जो लोग खुश हैं कि capital gain tax को 20 परसेंट से घटकर साढ़े 12 कर दिया गया है, उनके लिए मैं एक उदाहरण लाया हूँ। इस उदाहरण के माध्यम से हम समझ जाएंगे कि कैसे इंडेक्सेशन हटाना इस देश के इन्वेस्टर्स के लिए उसकी जेब पर डाका डालने जैसा है।

मैडम, फर्ज करिए कि आपने 2001 में एक करोड़ रुपए का एक मकान खरीदा। उस मकान की वैल्यू 6 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ती गई और वह मकान, जो आपने 2001 में एक करोड़ रुपए का खरीदा था, वह आज 4 करोड़, 17 लाख रुपए का हो गया। अब 2 सिनेरियो हैं। एक तो इंडेक्सेशन का सिनेरियो है, जिसमें आप उसे बेचें, तो उस पर टैक्स लगे और एक नया सिनेरियो, जिसमें अगर आप उसे बेचेंगे, तो नए रेट के अकॉर्डिंग उस पर टैक्स लगेगा। मैं पहले पुराने हिसाब से, इंडेक्सेशन वाले हिसाब से उस पर कितना टैक्स लगेगा, वह आपको बताना चाहता हूँ। वह मकान, जो आपने वर्ष 2001 में एक करोड़ रुपए का खरीदा था, वह आप आज 4 करोड़, 17 लाख रुपए में बेचती हैं। तो आपकी सेल प्राइस 4 करोड़, 17 लाख हुई, लेकिन आपकी purchase price, inflation-adjusted index purchase price एक करोड़ नहीं, लगभग 3 करोड़, 60 लाख के आसपास आती है। यानी आपका sale price minus purchase price, जो profit on sale है, वह 54 लाख रुपए होता है। उस 54 लाख रुपए पर 20 प्रतिशत के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। यानी कि इंडेक्सेशन वाले फार्मूले से आपको कुल टैक्स 10,80,000 रुपए देना पड़ता है। मैं राउंड ऑफ करके 11 लाख रुपए कहता हूँ। लेकिन जो नई व्यवस्था है, जिसमें इंडेक्सेशन आपसे छीन लिया गया है, उसमें सेल प्राइस 4 करोड़, 17 लाख, कॉस्ट प्राइस 1 करोड़ और मुनाफा 3 करोड़, 17 लाख और उस पर 12.5 परसेंट का टैक्स, यानी कि कुल मिलाकर आपका टैक्स 39,62,000 बनता है। यानी कि अगर आप आज नई व्यवस्था में वही एक करोड़ का मकान 4 करोड़, 17 लाख में बेचेंगे, तो आपको लगभग 40 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा, जबकि पुरानी व्यवस्था में आपको मात्र 11 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि 40 माइनस 11 करें, तो आपको मात्र 1 करोड़ रुपए के प्लाट की सेल पर लगभग 29 लाख रुपए का एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। यह है - इंडेक्सेशन का खेल। इसीलिए इंडेक्सेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए अति आवश्यक है। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि वह उसे न हटाए। आज मैं इस सदन में यह भविष्यवाणी करता हूँ कि अगर आपने इंडेक्सेशन वापस लागू नहीं किया, तो इस देश में तीन चीज़ें होने जा रही हैं। पहला, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट गिरने वाली है और लोग अपना ड्रीम होम कभी नहीं खरीद पाएँगे। दूसरा, प्रॉपर्टी डील्स की अंडरवैल्युएशन होगी और सब लोग सर्किल रेट पर प्रॉपर्टी

खरीदेंगे और बेचेंगे, लेकिन कोई उसकी असली कीमत नहीं बतायेगा। इस देश में जो थर्ड थिंग होने जा रही है, वह यह है कि रियल एस्टेट सेक्टर में भारी तादाद में ब्लैक मनी आने जा रहा है, अगर आपने इंडेक्सेशन के बारे में यह फैसला वापस नहीं लिया।

सरकार को मेरा पाँचवाँ सुझाव यह है कि आप फाइनेंशियल सेविंग्स को इंसेंटिवाइज करिए। डेट में, इक्विटी में, म्युचुअल फंड्स में, बैंक डिपॉजिट में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स और खास करके जो लोग 24 से 36 महीने से अधिक अपनी इन्वेस्टमेंट रखते हैं, उन्हें इंसेंटिवाइज करिए, टैक्स मत करिए, पेनलाइज मत करिए। मैं कहूँगा कि आने वाले समय में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गैन पर टैक्स अबॉलिश करने के लिए भी सोचना चाहिए, ना कि उसे सिर्फ कम करना चाहिए।

मेरा छठा सुझाव यह है कि review, revise and simply GST. GST, जिसे आज देशवासी गहरा संकट टैक्स या गब्बर सिंह टैक्स के नाम से जानते हैं, चाहे वह रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, हर चीज पर जीएसटी लगा-लगाकर हमने इस देश के इन्फ्लेशन पर भी जीएसटी लगा दिया। इससे सारी चीज़ें महँगी हो गईं। सरकार को मेरा सुझाव है कि इस जीएसटी के पूरे फ्रेमवर्क को कंप्रिहेंसिवली स्टडी करके रिवाइज कीजिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में जीएसटी कम कीजिए, ताकि हम ग्लोबली कॉम्पिटीटिव बन सकें। एमएसएमई सेक्टर, जो नौकरियाँ देता है, जिसमें छोटे उद्योग हैं, उसमें जीएसटी कम कीजिए और एसेंशियल कमोडिटीज, जैसे - दूध, दही, चावल, आटा, रोटी है, उन पर कम से कम जीएसटी विदड्रॉ कीजिए।

मेरा सातवाँ सुझाव यह है कि give more to states. India is a Union of States. स्टेटस की जेब में थोड़ा पैसा डालिए। हम सब कोलिशन पॉलिटिक्स के कंपल्शंस समझते हैं कि आपको बिहार को और आंध्र प्रदेश को ज्यादा पैसा देना था, लेकिन उन राज्यों ने, जिन्होंने आपको भरपूर वोट दिया, जैसे - गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ ने, जिन लोगों ने अपने राज्यों की लगभग सारी सीटें आपकी झोली में डाल दीं, उनसे क्या गलती हुई? आपने उन राज्यों को एक-एक झुनझुना दिया और बाकी दो राज्यों पर सब कुछ लुटा दिया। तो यह discriminatory federalism नहीं होना चाहिए, cooperative federalism होना चाहिए। मैं यह गुहार लगाना चाहूँगा। इस सरकार को सेस और सरचार्ज लगा कर पैसा वसूलने की एक बुरी आदत है। सेस और सरचार्ज सरकार का वह टैक्स है, जिसे उन्हें राज्यों के साथ बाँटना नहीं पड़ता है। वह डिविज़िबल पूल में नहीं जाता, इसलिए सरकार सेस और सरचार्ज लगा-लगा कर आम आदमी से पैसा वसूलती है। अगर केन्द्र सरकार एक सौ रुपए कमाती है, तो उसमें से 18 रुपए सेस और सरचार्ज के जरिए कमाती है, यानी मात्र 82 रुपए डिविज़िबल पूल में जाता है, जो राज्यों में बाँटा जाता है और 18 रुपए सीधे केन्द्र सरकार की जेब में जाता है। मैं अनुरोध करूँगा कि या तो सेस और सरचार्ज की इस प्रथा को बंद किया जाए या उसको भी डिविज़बल पूल में डाल कर उसे स्टेट्स के साथ बाँटे।

मेरा आठवाँ सुझाव यह है कि जीएसटी कंपनसेशन, जो राज्यों के लिए बंद कर दिया गया है, उसे कम-से-कम पाँच साल और दीजिए। कई ऐसे राज्य हैं, जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, आदि जिनकी अर्थव्यवस्था आज जीएसटी कंपनसेशन के पैरों पर खड़ी हुई है। आज हमारे बजट में इनकम का 10 से 15 प्रतिशत हिस्सा जीएसटी कंपसेशन से आता है। मैं

सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि कम-से-कम और पाँच साल जीएसटी कंपनसेशन देकर इन राज्य सरकारों की मदद की जाए।

मैडम, मैं अंत में यही एक बात बोल कर अपनी बात खत्म करूँगा कि इस बजट ने टैक्स बढ़ा-बढ़ा कर इस देश के आम आदमी का खून चूसने का काम किया है। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि डायरेक्ट टैक्स हो या इन्डायरेक्ट टैक्स, इस पूरी व्यवस्था पर एक बार फिर से गौर फरमाया जाए। जो मैंने शुरुआत में कहा था, उसे मैं दोहराऊँगा कि अगर हम दस रुपए कमाते हैं, तो उस पर तीन या साढ़े तीन रुपए इनकम टैक्स लगता है, दो से ढाई रुपए जीएसटी खा जाता है, डेढ़ रुपए का कैपिटल गेन टैक्स लगता है, आधे पैसे का सेस और सरचार्ज लगता है, यानी दस रुपए में से छः से सात रुपए सरकार की जेब में चले जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप साल में दस रुपए कमा रहे हैं, तो आपकी सात से आठ महीने की कमाई सरकार ले जाती है और मात्र तीन या चार महीने की कमाई आपकी जेब में आती है। उसके बाद उस पर भी अन्य प्रकार के टैक्स लगते हैं, लेकिन उसके बदले में हमें कोई सुविधाएँ नहीं मिलती हैं, न ट्रांसपोर्ट, न हेल्थ केयर, न कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि और बड़े-बड़े विकसित देशों - यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन कंट्रीज़, जो high-tax regimes मानी जाती हैं, उनमें नागरिकों को सुविधा दी जाती है। लेकिन उसके बदले दिल्ली में, हिन्दुस्तान में, देश भर में कोई ऐसी सुविधा केन्द्र सरकार नहीं देती है। इसीलिए यह कहा जाता है that we impose taxes like the Europeans do to get services like sub-Saharan countries. मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि वह इस टैक्स फ्रेमवर्क, डायरेक्ट टैक्स हो या इन्डायरेक्ट टैक्स हो, उसका भी एक comprehensive review करे, बहुत-बहुत शुक्रिया।

उपसभाध्यक्ष (सुश्री कविता पाटीदार) : माननीय सदस्य श्री देबाशीष सामंतराय। सामंतराय जी, यह आपकी मेडन स्पीच है।

SHRI DEBASHISH SAMANTARAY (Odisha): Madam, Vice-Chairperson, first I want to thank my leader, Naveen Patnaik*ji*, for sending me to this august House to be among such stalwart politicians, such great leaders, and I thank the Chair for allowing me to make my first maiden speech. I stand here to discuss on the Budget. Obviously, from the Party's point of view, I am not in support of this Budget for various reasons. Both in the President's Address and in the Budget presented by the hon. Finance Minister, the regional aspirations of this country were completely neglected. It was nowhere shown as to where in this country's federal structure of democracy do the regional entities and the regional States stand. I will restrict myself to Odisha. But, as regards the mandate of this Modi 3.0 Government, I think, probably, the Ruling Party is not reading it correctly. If you see, the Lok Sabha has 204 Members from the regional parties. It is a big chunk and it only goes to show that regional parties play a very important role. This Government cannot read the writings

on the wall, and they all tom-tommed about the Modi 3.0 Government, but that is not, in reality, a single party Government.

If the regional aspirations are not addressed to, I am sure, the message is clear; this Government will be out very soon.

There is 'the betrayal of Odisha.' I am sure, all the Members, even the BJP Members will appreciate this. Look at the betrayal of Odisha by this Government. They got 20 MPs. For 20 MPs from Odisha, today Modiji is sitting in that No. 3 -- No. 3, as Prime Minister. If 20 would have been reduced by 10-12, where would have they been? They have got a mandate but 'zero' for Odisha. In no field -- some pittance, they gave in tourism — they have given to Odisha even when a State believed in a change, believed that probably, they will do better than Naveen Patnaik. Naveen Patnaik's tenure as the Chief Minister for five terms left the State with a surplus of Rs. 46,000 crores. It was not bankrupt; it was not as bankrupt as Andhra was. In spite of that, in spite of our fiscal management, repeatedly, we have been neglected even during our five terms. I don't know how many times, they came running to Naveen Patnaik's knees for their Government's sake. We supported them. They forgot that. Just to win an election, such wrong narratives, such unparliamentary aspersions on a leader like Naveen Patnaik about this health, what standard has the Indian politics gone to? Okay; you have won. We accept the verdict. But then what have you done for Odisha? Is there a revision of the coal royalty which you have been seeking for so long? Where are the Highways? If you go to the State, there is not a single National Highway you can travel on. But, with pride, I say, look at our State Highways. Look at the Biju Expressway. It is an example in this country. Look at all the State roads. I don't know why there is this regional imbalance. Look at Eastern India. There is neglect of Bengal, neglect of Odisha, neglect of Chhattisgarh, neglect of Jharkhand. Bihar now ठीक है, नहीं तो बिहार आपको पलट देगा, इसलिए बिहार को अभी मस्का लगाओ। So, there is this aspect. What kind of a Budget is this? This Budget is just like appeasing two States. The State of Odisha, under Naveen Patnaikji, from the bottom level of poverty has come to the top. It has helped security in the State. Under him, the food production went to surplus, from minus, and the State sends foodgrains. When the biggest national disaster happened in 1999, the State was devastated. The people were sending from clothes to ration to Odisha because it was so badly destroyed by the supercyclone. In the next 20-25 years, when other States faced the Covid disaster, they needed oxygen. When we were getting old clothes for help from others, we sent oxygen to many States. This is how he had managed, and yet there is no mention of Odisha anywhere.

We need to reach telecommunication network everywhere as we have 22 per cent tribal population and we do have the Left-Wing Extremism to tackle with. We have been asking the Central Government, after highways and railway connectivity, that telecommunication has to reach every nook and corner of the State. Banks need to be opened up everywhere in Odisha but this demand is, repeatedly, falling in deaf ears. When it comes to floods and national disasters, I think, no other State has so many natural disasters as Odisha has. We have never been given adequate support by the Centre and when the Central Government offered something meagre, Naveen *Babu* could tell them in the face that the State has its own resources; we don't need your pittance. You gave money for flood mitigation to six States. I won't name them; they deserve it. But what did they give to Odisha? When it comes to Polavaram project, it is funded by the Centre. What happens if it begins, Koraput will be submerged in water. There is a river which originates in Odisha. But there is no discussion about Mahanadi with us. Chhattisgarh has an engine, the Centre has an engine and Odisha has an engine. There are three engines, still it is not working. I don't think there is any such thing like engine. Probably, these engines which run in Darjeeling, etc., are redundant from the British Era. There are major minerals in Odisha -- iron ore, coal, bauxite, manganese and chrome. If coal does not go from Odisha to other States, I think, 50 per cent of this country will have no electricity. The whole country won't be able to produce steel without iron ore and aluminium without bauxite. There are Jharkhand, Bihar, Bengal and Odisha which contribute a major source of minerals for this country, which go for industrialisation all over. What do we get in return? We have been repeatedly asking for royalty revision. Of course, I thank the Supreme Court. They have passed a monumental judgement saying that States can levy their own taxes on minerals and that was Naveen Patnaik's demand to the Centre which was never considered. But, today, we thank the Supreme Court for giving the States this right to levy taxes on the properties of the States where minerals are found. We are contributing to the national exchequer in so many ways. It is Odisha's minerals on which the Centre receives crores and crores of rupees. But what do they give to Odisha? Look at the revenue of the Railways. Evacuation of minerals from Odisha earns a whopping amount of money for the railways. What do they give us? What is there in this Budget itself? Our Railway Minister should be grateful to BJD because he has come here in this House because of BJD. But where is Odisha? On tendu leaves, you have 18 per cent GST. What is this? Can somebody put some sense? Tendu leaves are collected by means of hard labour. You have 1 per cent GST on diamond, 3 per cent GST on gold. डायमंड वाले एंटीगुआ में भाग गए, उनको आप पकड़ कर नहीं ला पा रहे हैं और इधर इंश्योरेंस में 18 परसेंट, लाइफ

इंश्योरेंस में 18 परसेंट, मेडिकल इंश्योरेंस में 18 परसेंट, यह क्या हो रहा है? *This is absolutely insensitive and irresponsible. This is not democracy. This is autocratic. We are a federal democracy where States need to be heard. It is not that we are asking for something, or, we are begging. Give us our rights. We contribute, but what do we get in return after you get a mandate? It is zero; zero to Odisha. This Government just talks double engine and triple engine. I don't know whether they have heard or not, but they are redundant engines now. I don't know if they understand. They were like Second World War engines or something. Today, in this House, the Opposition is more than the ruling side. You don't allow the opposition to talk. Let the President's election come and then you will see. It is not far away. It is not only my view about neglecting of States, but there are so many regional parties here. We know our neglect. Look at Bengal. It does not exist as a State for them. Look at Maharashtra, which gives the highest tax revenues to the country. It is only Gujarat for them. I met some people from Uttar Pradesh. They said that Uttar Pradesh has been taken over by Gujaratis. अयोध्या के contract गुजराती को, बनारस में गुजराती को. So, somebody has to correct this system. I am sure, after this mandate, where Modi Government is just managed, the writing on the wall is very clear. If they don't mend their ways, they will definitely be thrown out in the next election.

THE VICE CHAIRPERSON (MS. KAVITA PATIDAR): Please conclude, hon. Member. Your time is over.

SHRI DEBASHISH SAMANTARAY: I would conclude by saying that the regional aspirations should be addressed. There is time; there is chance. Even a friend from us spoke about it. Please go back to your tables. Take this country as a whole; take this democracy. Don't behave like rightists. There is always a left, a centre and a right in a democracy. We are not only rights here. Therefore, before I conclude, I would like to say that I don't support this Budget, and I request with humility that this Government should realise the regional aspirations of this country. Thank you.

उपसभाध्यक्ष (सुश्री कविता पाटीदार): माननीय सदस्य, श्री संजय यादव।

SHRI SANJAY YADAV (Bihar): Thank you, Madam, for giving me this opportunity to speak. It is my privilege and pleasure to be in this august House in the presence of learned politicians from across the country cutting across all the parties and

* Expunged as ordered by the Chair.

ideologies. मुझे यह जिम्मेवारी और अवसर देने के लिए मैं सामाजिक न्याय के पुरोधा श्री लालू प्रसाद यादव जी और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। उपसभाध्यक्ष महोदय, इस बजट के लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बजट खाली पेटों के लिए नहीं, सिर्फ धन्ना सेठों के लिए है। यह बजट उनके लिए नहीं, जो मजबूर और गरीब हैं, यह बजट उनके लिए है, जो मजबूत और सत्ता के करीब हैं। यह बजट वंचित, उपेक्षित, उत्पीड़ित, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक के विकास के लिए नहीं, बल्कि उनके उपहास के लिए है। इस बजट में यह नहीं बताया गया है कि पूरे देश में बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी की दर क्या है? हमारे कितने ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं, हमारे कितने इंजीनियर्स बेरोजगार हैं, तो इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि युवाओं के सपनों का मरघट है यह बजट, असत्य और जुमलों का जमघट है यह बजट।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत बातें हुईं। हम विश्व की पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था हैं। हम इससे ऊपर भी जा सकते हैं और समय के साथ जाएंगे भी। लेकिन पांचवें नम्बर की अर्थव्यवस्था होने की खुशफहमी में हम यह भूल जाते हैं कि प्रति व्यक्ति आय में हम 197 देशों में से 142वें नम्बर पर हैं। प्रति व्यक्ति आय में हम अफ्रीकी देश अंगोला से भी कम हैं। देश में सिर्फ एक प्रतिशत लोगों के पास देश की 40 प्रतिशत सम्पत्ति है और देश के 10 प्रतिशत लोगों के पास देश की 77 प्रतिशत सम्पत्ति है, यानी हमारे देश में आय और सम्पत्ति का एक समान वितरण नहीं है। महोदया, हमें इस दिशा में भी सोचना होगा।

मानव प्रगति और आर्थिक प्रगति दोनों अलग-अलग विषय हैं। मानव प्रगति में हम मानवीय पहलुओं को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, मानवीय प्रगति में हम लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, बराबरी और गरीबी को आंकते हैं, लेकिन आर्थिक प्रगति में हम सिर्फ धन के संचय पर ही केंद्रित रहते हैं। इसलिए धन के संचय के साथ-साथ मानवीय विकास की भी बातें होनी चाहिए।

महोदया, इस बजट में किसानों को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं था। किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिल पाता, इस बजट में एमएसपी को लीगलाइज करने की कोई बात नहीं है। ये लोग फसल की कीमत 100 रुपए बढ़ाकर कहते हैं कि हमने किसानों का भला किया है, लेकिन ये नहीं बताते कि खाद की बोरी की कीमत 200 रुपए बढ़ा दी है। इसके साथ ही बोरी का वजन भी घटा देते हैं।

महोदया, बिहार के विशेष पैकेज को लेकर काफी बातचीत हुई है। सब लोगों ने कहा है कि बिहार को पता नहीं अलग से क्या मिल गया, उसको विशेष पैकेज दे दिया है। इन्होंने बिहार के विशेष पैकेज की री-पैकेजिंग की री-पैकेजिंग और फिर री-पैकेजिंग की, नई री-पैकेजिंग की है। यह वही बात हुई कि चार आने को एक रुपया बता देने से चार आना एक रुपया नहीं होता, वह चार आना ही रहता है। मैं बिहार के पैकेज को लेकर यही कहना चाहूंगा कि सिलेबस और किताब वही है, सिर्फ उसका जिल्द बदला है। हर साल ये बिहार के विकास को लेकर सिर्फ जिल्द बदलते हैं, सिर्फ रैपर चेंज करते हैं और कुछ नहीं बदलता है। वर्ष 2015 में आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने काफी ड्रेमेटिक अंदाज में बिहार के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की थी, करीब 1 लाख, 25 हजार करोड़ रुपए की और 40 हजार करोड़ रुपए उसमें अन्य निवेश, जैसे cherry on cake होता है, वैसे ही 1 लाख, 25 हजार करोड़ के अलावा 40 हजार करोड़ उन्होंने विशेष निवेश के लिए निर्धारित किए थे, इन फैक्ट आवंटित किए थे। अब इस बजट में इन्होंने हाईवेज के लिए 26 हजार करोड़ रुपए बिहार के लिए आवंटित किए हैं और 2015 में 54,713 करोड़ रुपए आवंटित किए थे।

हम पूछना चाहते हैं कि जो उस वक्त 54,713 करोड़ रुपए आपने बिहार के हाईवेज के लिए निर्धारित, आवंटित किए थे, उसका क्या हुआ? अब आप 26 हजार करोड़ रुपए दोबारा से दे रहे हैं। उस वक्त 2015 में बिहार के एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए आपने 2,700 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इस बजट में फिर आप नए एयरपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। उस बजट में आपने ढाई सौ करोड़ रुपए रक्सौल में एयरपोर्ट के विकास और निर्माण के लिए निर्धारित किए थे। महोदया, वहां पर आज तक 9 वर्ष में एक ईंट भी नहीं लगी है। फिर आप एयरपोर्ट के लिए धन आवंटित कर रहे हैं। आपने बांका में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के लिए 2015 में 20 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए, फिर अब बांका से बगल वाले जिले भागलपुर में, जो कि उससे सटा हुआ है, अब इसके लिए आपने 21 हजार, 400 करोड़ रुपए थर्मल पावर प्लांट के लिए आवंटित किए हैं। आपने 2015 में बांका में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के लिए 20 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए थे और अब आप 21 हजार 400 करोड़ रुपए भागलपुर के लिए आवंटित कर रहे हैं। जिला चेंज हो गया, 20 हजार करोड़ से 21 हजार, 400 करोड़ रुपए हो गया, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (**सुश्री कविता पाटीदार**): प्लीज, आप लोग अपनी सीट से बैठे-बैठे मत बोलिए। उनको बोलने दीजिए।

श्री संजय यादवः महोदया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की हमारी पुरानी मांग है। 2002 में तत्कालीन मुख्य मंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी। तब से लेकर अब तक हमारी लगातार यह मांग रही है। अभी कुछ दिन पूर्व नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई, संस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, सतत विकास के लक्ष्य का जो सूचकांक था, वह प्रकाशित हुआ। मैं सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि बिहार के संदर्भ में आपको नीति आयोग की वह रिपोर्ट पढ़नी चाहिए।
हम उसमें किन-किन सूचकांक में पीछे हैं। महोदया, सतत विकास के लक्ष्य के जो सूचकांक हैं, उनको पैमाना मानते हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए सभी को एक स्वर से मांग उठानी होगी।

महोदया, बिहार में 15 वर्षों से अधिक एनडीए की सरकार रही है, 10 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इन्हीं के नीति आयोग के पैमाने पर बिहार समावेशी विकास की दौड़ से बाहर है। बिहार इन 15 वर्षों और 10 वर्षों में सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में बिल्कुल फिसड्डी बना हुआ है और 'सबका साथ-सबका विकास' सिर्फ एक जुमला मात्र रह गया है। एक तरफ नीति आयोग के एसडीजी गोल सूचकांक में जहाँ राष्ट्रीय औसत 71 है, वहीं बिहार का सबसे नीचे 57 है और यह ईयर ऑन ईयर नीचे जा रहा है। गरीबी उन्मूलन में बिहार का स्कोर देश में सबसे न्यूनतम 39 है, जबकि राष्ट्रीय औसत 72 है।

महोदया, शून्य भुखमरी में भी बिहार सबसे नीचे है। इसमें बिहार का स्कोर 24 है। क्वालिटी एजुकेशन और लैंगिक समानता में भी बिहार देश में सबसे पीछे है, असमानता कम करने के क्षेत्र में भी बिहार के अंक कम हैं। इस तरह से यदि कुल मिलाकर देखें, तो राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में बिहार कहीं नहीं दिख रहा है। राज्य की नीतियाँ बगैर लाँग टर्म गोल्स के साथ बनाई जा रही हैं, उनका क्रियान्वयन भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। किस तरह से पुल गिर रहे हैं - यह सबने देखा है।

महोदया, पिछले दस वर्षों में बिहार को केंद्र सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला है, इसलिए हम कहेंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अवश्य ही देना चाहिए और यह विशेष पैकेज़ नए रैपर में बदलकर मत दीजिए, आप उसे अभी आवंटित कीजिए और एक टाइम लिमिट के साथ आवंटित कीजिए कि इस समय में, इस पर्टिकुलर सैक्टर में आपको यह धनराशि मिली है, इसलिए उसका क्रियान्वयन और इम्प्लिमेंटेशन हो।

उपसभाध्यक्ष महोदया, जैसाकि मैंने कहा है कि हमारा देश युवाओं का देश है, हमारे देश में सबसे अधिक आबादी युवाओं की है, लेकिन यहाँ बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा है। विगत 10 सालों में हमारे देश में बेरोजगारी दर 5.04 प्रतिशत से बढ़कर 9.02 हो गई है, जो कि अत्यधिक चिंताजनक बात है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े तो सरकार ने बजट में नहीं दिए हैं, लेकिन हमारे पास जो आंकड़े हैं, उनके मुताबिक आज देश में जो बेरोजगार लोग हैं, उनमें 83 परसेंट बेरोजगार युवा हैं। महोदया, जो आधे से अधिक इंडियन ग्रेज्युएट्स हैं, वे बेरोजगार हैं, यानी जो हर दूसरा ग्रेज्युएट है, वह बेरोजगार है। महोदया, पढ़े-लिखे युवाओं में बेरोजगारी दर 65.07 परसेंट है। ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 17.05 परसेंट युवाओं के पास ही काम है। यानी कि गाँव में रहने वाले, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 83 फीसदी युवा बेरोजगार हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। महोदया, ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी दूर नहीं की जा सकती है। बिहार में हमारी 17 महीने की महागठबंधन की सरकार ने उसे दूर करके दिखाया है। बिहार में तेजस्वी मॉडल के तहत महज 17 महीनों में हमने 4 लाख से अधिक सरकारी नौकरियाँ दीं, 3 लाख से अधिक सरकारी नौकरियाँ प्रक्रियाधीन करवाईं। अगर बिहार जैसा कम संसाधन वाला पिछड़ा प्रदेश 17 महीनों में एक युवा उप मुख्यमंत्री की इच्छाशक्ति के दम पर 4 लाख नौकरियाँ दे सकता है, 3 लाख नौकरियाँ प्रक्रियाधीन करवा सकता है, तो हम देश भर में 10 सालों में करोड़ों नौकरियाँ क्यों नहीं दे पाए, जबकि देश में 30 लाख पद रिक्त हैं? उन पदों को भरने की दिशा में भी इस बजट में कोई जिक्र नहीं है।

[**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी)** *पीठासीन हुईं।*]

उपसभाध्यक्ष महोदया, पूरा देश यह जानता है कि लालू जी के शासन से पहले बिहार में गैर बराबरी का बोलबाला था। पिछड़े, गरीब, दलित, वंचित वर्ग के लोग सामाजिक पायदान में बड़े लोगों के सामने खाट पर नहीं बैठ सकते थे, लेकिन लालू जी ने सामाजिक न्याय के जरिए बराबरी का कुआँ और बराबरी की खाट दी और अब हमारे नेता तेजस्वी जी का मिशन आर्थिक न्याय के जरिए इन लोगों को बराबरी की खाट देने का है।

उपसभाध्यक्ष महोदया, इस सरकार का क्या कहें? दस वर्ष पूर्ण बहुमत के शासन के बाद भी ये अपने भाषणों और बजट में अपनी उपलब्धियों के बखान की बजाय सिर्फ विपक्ष की निंदा और उसकी आलोचना में अपना समय ज़ाया करते हैं। शायद विपक्ष की निंदा करने से इन्हें अपनी शासकीय कमियों, खामियों, असफलताओं को छिपाने में मदद मिलती होगी, लेकिन इस विपक्ष की आलोचना और निंदा से जनता का कोई भला नहीं होने वाला है और जनता ने इस चुनाव में यह अच्छे से बता भी दिया है। महोदया, जनता मुर्दों की नहीं, मुद्दों की बात करना चाहती है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये गड़े मुर्दे उखाड़ने में लगे रहते हैं और जनता के मुद्दों को दफन कर देते हैं। अभी

देश में क्या हाल हो रहा है? हम सबने देखा कि अभी उत्तर प्रदेश में हालिया घटना क्या हुई। क्या खतरनाक ट्रेंड हो रहा है, कैसा खतरनाक बंटवारा कर रहे हैं! ये फल वालों को नाम की तख्ती लगाने की ताकीद कर रहे हैं। एक फल बेचने वाला अपना फल बेचने को स्वतंत्र नहीं, तो समझो उस जगह लोकतंत्र नहीं। हम अपना भविष्य कहाँ ले जा रहे हैं, छात्रों-युवाओं और आने वाली पीढ़ी को क्या सिखा रहे हैं? वह दिन दूर नहीं जब ये लोग बच्चों को 'अ' से अनार, 'आ' से आम की जगह 'अ' से अनिल का अनार और 'आ' से आसिफ का आम पढ़ाना शुरू कर देंगे। महोदय, सत्ता के लिए ये सबको सता रहे हैं। यह धर्म के नाम पर बंटवारा, जाति के नाम पर बंटवारा न हमारे देश की संस्कृति है, न यह हमारी सामाजिक विरासत है और न ही हमें यह सब मानवता और इन्सानियत सिखाती है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर इंडिया गेट है। आप इंडिया गेट पर जाकर देखिए, वहाँ पर जो शहीदों के नाम लिखे हैं, उनमें सबसे अधिक मुसलमानों के नाम हैं, सिखों के नाम हैं, किसानों के परिजनों के नाम हैं। इस देश की जंग-ए-आज़ादी में जिन्होंने सबसे अधिक कुर्बानी दी, आप उन्हें ridicule करते हैं, आप उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने भी कहा है कि किसी के दीन की तौहीन करने से बड़ा कोई और गुनाह नहीं है। महोदय, लोगों को धर्म के नाम पर बांटना भी सबसे बड़ा अधर्म है। मानवता को बांटने वालों को छांटना होगा और जनता ने इसकी शुरुआत इस लोक सभा चुनाव से कर दी है। इस चुनाव में 64 करोड़ मतदाताओं में से 41 करोड़ मतदाता सामाजिक न्याय, धर्म निरपेक्षता, अमन, चैन, शांति और संविधान की इस धारा के साथ खड़े रहे। अंत में, मैं इतना कहना चाहूँगा कि इन जय धनवान बोलने वालों को हम जय संविधान बोलते हैं और अपनी बात को समाप्त करते हैं, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, सत्यमेव जयते।

THE VICE CHAIRPERSON (SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI): Shri C.Ve. Shanmugam. He is not there. Dr. Medha Vishram Kulkarni. This is your maiden speech.

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी (महाराष्ट्र): धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदया। मैं अपना भाषण मराठी में देना चाहूंगी।

THE VICE CHAIRPERSON (SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI): I request everyone on this side to please be silent. Please listen to her maiden speech. Please continue.

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी: * "मैं माननीय नरेन्द्र मोदी जी को उनके तीसरे कार्यकाल के लिए हार्दिक बधाई देती हूं। साथ ही मैं माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को भी इस बजट को बहुत अच्छे तरीके से पेश करने के लिए बधाई देती हूं। मेरा मानना है कि यह बजट निश्चित रूप से

* English translation of original speech delivered in Marathi.

देश के सभी राज्यों को प्रगति की दृष्टि से, भारत को विकास के पथ पर, प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए एक पूरक के रूप में काम करेगा। राष्ट्रपति महोदया ने अपने संबोधन में कहा, ये सदी भारत की सदी है, यह बजट विकास भी और विरासत भी के उद्देश्य से तैयार किया गया है, जो इस मुहावरे को सार्थक करता है। इसमें बिना किसी प्रकार के पाखंड के देश के सभी राज्यों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। देश के विकास में हर राज्य शामिल है, मैं महाराष्ट्र से आती हूं। महाराष्ट्र एक बहुत ही प्रगतिशील राज्य है जहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक बार तत्कालीन मुगल सरकार, भारत पर अत्याचार करने वाले अत्याचारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और हिंदू स्वराज की स्थापना की थी। मैं महाराष्ट्र से आती हूं जहां इस स्वराज के झंडे को श्रीमंत बाजीराव पेशवा ने बुलंद किया था। महाराष्ट्र की इसी धरती ने देश को स्वतंत्रता सेनानी सावरकर, लोकमान्य तिलक, अहिल्याबाई होल्कर, डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर आदि दिए। हम सभी को निश्चित रूप से महाराष्ट्र पर गर्व है, जिसने देश को ऐसी महान हस्तियां दी हैं। और इसी महाराष्ट्र के लिए माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा इस बजट में बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है। लेकिन जिन लोगों को पीलिया होता है उन्हें हमेशा पीला रंग दिखाई देता है। दरअसल खोट उनकी नजरों में है, उनके नजरिए में है और इसीलिए उन्हें दुनिया पीली दिखती है। लेकिन उन्होंने ये आरोप लगाया, इस सदन के एक माननीय सदस्य हैं, चैनल पर बोलते हुए वे हमेशा जानकारी देते हैं और हर बार गलत जानकारी देते हैं। उन्होंने इस तरह से बेहद हल्का बयान दिया कि यह बजट लोकसभा नतीजों से प्रभावित है। मैं उनका नाम नहीं लूंगी। साथ ही उन्होंने यह भी बयान दिया कि इस बजट में सरकार ने पिछले दस साल के बजट में महाराष्ट्र को क्या दिया है? दरअसल, हमें ऐसे लोगों की मानसिकता के बारे में बात नहीं करनी चाहिए. लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि हम महाराष्ट्रवासी जो छत्रपति शिवाजी महाराज को आदर्श मानते हैं और माननीय प्रधान मंत्री जो उसी आदर्श के साथ देश में काम कर रहे हैं, उनके मन में ऐसा विचार कभी नहीं आएगा। मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूं कि यह विचार केवल औरंगजेब फैन क्लब में ही आ सकता है।"**...(व्यवधान)...**

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल (महाराष्ट्र): मैडम **...(व्यवधान)...**

THE VICE CHAIRPERSON (SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI): Madam, please speak on the Budget. ...(*Interruptions*)...

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी : मैंने किसी के ऊपर...(**व्यवधान**)...किसी पर्टिकुलर ...(**व्यवधान**)...

THE VICE CHAIRPERSON (SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI): Please be seated. ...(*Interruptions*)... Let her speak. ...(*Interruptions*)...

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी: अगर कोई ऐसा आरोप कर सकता है, तो खुद को जांचना चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE CHAIRPERSON (SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI): Madam, one minute. ...(*Interruptions*)... Please stick to the Budget.

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी : "महाराष्ट्र में छह लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट केंद्र की ओर से महाराष्ट्र के लिए दिए गए हैं। मैं रेलवे से शुरू करती हूं। रेल मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र के लिए दिया गया बजट 15 हजार, 940 करोड़ रुपये है। इस सरकार ने महाराष्ट्र के लिए इतना बड़ा प्रावधान किया। 2009 से 2014 तक की अवधि में जो सरकार थी, उसने सिर्फ 1100 करोड़ रुपये दिये। उससे तेरह गुना प्रावधान इस सरकार ने रेलवे के लिए किया है। 2009 से 2014 के बीच शून्य किलोमीटर तक विद्युतीकरण किया गया। कोरोना टीकाकरण शून्य हो गया है, शून्य नहीं है, आपके समय में शून्य है। लेकिन अब मेरे राज्य में 351 किमी की रेलवे विद्युतीकरण परियोजनाएं चल रही हैं। महाराष्ट्र में 5847 किमी लंबी 41 रेलवे परियोजनाएं नई शुरू की गई हैं। इसके लिए 81 हजार, 850 करोड़ रुपये का फंड रखा गया है। अमृत भारत योजना के तहत महाराष्ट्र में 128 रेलवे स्टेशनों का विकास किया गया है। पहले देखा जाए तो ट्रेन से यात्रा करना नारकीय यातना थी। अब देखा जाए तो सभी रेलवे स्टेशन साफ सुथरे हैं। हवाई अड्डों की तरह रेलवे स्टेशनों की सूरत भी बदल गई है। रेलवे अंडरपास और ओवर ब्रिज की संख्या 921 है। रेलवे पर इतनी बड़ी धनराशि खर्च की गई है। अब मैं आपको हवाई अड्डों के बारे में बताती हूं। आपने सुना ही होगा उड़े देश का आम नागरिक। प्रत्येक नागरिक को हवाई यात्रा करने, यथाशीघ्र अपने इच्छित स्थान पर पहुँचने, व्यवसाय वृद्धि के लिए कम से कम दूरी तय करके अपने इच्छित स्थान पर पहुँचने का अधिकार है। यही कारण है कि माननीय प्रधान मंत्री के नेतृत्व में सरकार ने हवाईअड्डों का निर्माण किया है, और महाराष्ट्र इससे वंचित नहीं है। अगर हम महाराष्ट्र के बारे में सोचें तो शिर्डी होगा, कोल्हापुर होगा, कई नए हवाई अड्डे बनाए गए हैं। साथ ही पुणे हो या नागपुर, हवाईअड्डों के विस्तार ने भी यह गति पकड़ी है। पुणे जिले के पुरंदर में जल्द ही एक नया हवाई अड्डा बनाया जाएगा। नवी मुंबई में भी एयरपोर्ट बनाया जाएगा। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगी कि केंद्र सरकार के माध्यम से बड़ी मात्रा में धन उपलब्ध कराया जा रहा है। आइए मेट्रो के बारे में सोचें। अब इस जगह पर बहुत कम लोग हैं। मैं पुणे से आई हूँ। पुणे शहर में एक तत्कालीन सांसद थे। इन सांसद का नाम आपने कॉमनवेल्थ गेम्स घोटालों में सुना होगा। इन सांसद ने हर बार पुणे को धोखा दिया, हर बार उन्होंने वादा किया कि हम पुणे में मेट्रो लाएंगे, हम मोनोरेल लाएंगे। हर साल वादे किये गये, धन मुहैया कराया गया और फिर मुंह फेर लिया। उन्होंने ये काम किया और इसकी वजह से पुणे का ट्रैफिक पूरी तरह से बाधित हो गया है। ये सफ़ाई कब संभव हुई, कब सफ़ाई शुरू हुई, 2014 में केंद्र में माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार थी और जब राज्य में देवेन्द्र फड़णवीस की सरकार आई तो पुणे की शक्ल बदलने की कोशिशें शुरू हो गईं। आज पुणे में मेट्रो नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, केंद्र सरकार की ओर से मेट्रो के लिए 814 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुंबई मेट्रो के लिए 1087 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 2014 से पहले महाराष्ट्र में मेट्रो नेटवर्क केवल 11 किमी था। सिर्फ 11 किलोमीटर, और अब मैं बताना चाहती हूं कि महाराष्ट्र में मेट्रो की लंबाई तीस किलोमीटर है। केंद्र सरकार के माध्यम से नागपुर मेट्रो के लिए 683 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। निकटवर्ती सुविधाओं के लिए कितनी धनराशि प्राप्त हुई? नरेन्द्र

मोदी सरकार ने मुंबई के लिए दो लाख करोड़ का प्रावधान किया है. एमएमआर ग्रीन अर्बन प्रोजेक्ट के लिए 150 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ये आंकड़े मैं जानबूझ कर बता रही हूं क्योंकि हर बार जिनको पीलिया हो जाता था, वे बाहर जाकर चैनल वालों को बताते थे और चैनल वालों के माध्यम से वे लोगों के दिमाग में ये बात भर देते थे कि महाराष्ट्र को कुछ नहीं दिया गया, महाराष्ट्र को कुछ नहीं दिया गया। मैं बताना चाहती हूं कि महाराष्ट्र को क्या दिया गया है और इसलिए मैं कहती हूं कि एमएमआर ग्रीन अर्बन प्रोजेक्ट के लिए महाराष्ट्र को 150 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। दिल्ली देश की राजधानी है और मुंबई देश की वित्तीय राजधानी है। इन दोनों को जोड़ने वाली एक बहुत ही भव्य परियोजना, मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, के लिए केंद्र सरकार के माध्यम से 499 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। MUTP-3 मुंबई के आसपास के उपनगरों, विरार, दहानू को जोड़ने के लिए 64 किलोमीटर लंबा गलियारा है और केंद्र सरकार ने 908 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।" ...(**व्यवधान**)... Let me speak. *...(Interruptions)...* Let me speak. *...(Interruptions)...*

THE VICE CHAIRPERSON (SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI): Please. *...(Interruptions)...* I can handle that. *...(Interruptions)...* I can handle my job. *...(Interruptions)...*

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी : "बस आप जोड़ें, पंजीकरण करें और फिर मुझे बताएं कि यह कितना था। ठाणे बोरीवली टनल को भारत की सबसे बड़ी परियोजना बनाने के लिए केंद्र सरकार के माध्यम से 16000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बंदरगाह परियोजना एक अत्यंत महत्वाकांक्षी एवं दूरदर्शी परियोजना है। प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना और सागरमाला परियोजना के तहत महाराष्ट्र को मिले फंड की बात करें तो सागरमाला योजना के लिए महाराष्ट्र को 1 लाख, पांच हजार करोड़ रुपये मिले हैं. और उसमें से 76 हजार, 220 करोड़ रुपये बंदरगाह के विस्तार के लिए उपलब्ध कराये गये हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरे राज्य को किसी एक प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार से इतनी बड़ी धनराशि मिली हो। प्रधान मंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री जी को हार्दिक बधाई एवं हार्दिक धन्यवाद। आइए मैं आपको बताती हूं कि इस प्रोजेक्ट के साथ क्या होने वाला है। यह परियोजना पालघर जिले में तट पर स्थित है। वहां एक गहरे समुद्री बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है और यह न केवल महाराष्ट्र बल्कि देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह होगा। उस स्थान पर बीस फीट लंबाई के 24 हजार कंटेनरों का कारोबार होता रहेगा और यहां दो लाख नौकरियां पैदा होंगी। आज नौकरियों की कोई कमी नहीं है, युवा रोजगार के लिए आकर्षित हो रहे हैं। इधर किसी ने हाल ही में कहा कि कैंटीन में नौकरी के लिए 15 पदों के लिए इतने सारे आवेदन आए हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी इतनी नौकरियाँ क्यों उपलब्ध हैं? युवाओं को सिर्फ अपनी तत्परता दिखानी चाहिए। यहां इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है।"

श्रीमती जया अमिताभ बच्चन : महोदया ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल : महोदया ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी) : आप बैठिए। **...(व्यवधान)...**

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी : मैं महाराष्ट्र पर बात कर रही हूँ, आपको सुनना पड़ेगा। **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी): यह उनकी maiden speech है। **...(व्यवधान)...**

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी: मैं महाराष्ट्र पर जवाब दे रही हूँ। आपको सुनना पड़ेगा। **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी): रजनी जी, ...(**व्यवधान**)... रजनी जी, आपको समय मिलेगा, तब आप उनका जवाब दीजिएगा। ...(**व्यवधान**)...

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी: महोदया, आप मेरा समय स्टॉप कीजिए। **...(व्यवधान)...** मेरा समय स्टॉप कीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी): आप बोलिए। **...(व्यवधान)...** आप बोलिए।**...(व्यवधान)...** Madam, speak on the Union Budget. असैम्बली की बातें यहाँ पर नहीं होंगी।**...(व्यवधान)...**

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी; मैडम, यह यूनियन बजट पर है, आप सुन लीजिए, देख लीजिए।....(**व्यवधान**)...

THE VICE CHAIRPERSON (SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI): Please speak on the Budget. ***...(Interruptions)...*** Prafulji, please be seated. ***...(Interruptions)...*** Please be seated. ***...(Interruptions)...*** Yes, please. ***...(Interruptions)...*** Please. ***...(Interruptions)...*** You can speak in the Assembly, we are in the Rajya Sabha. ***...(Interruptions)...***

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी : "इससे रोजगार भी पैदा होंगे और अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। इस स्थान पर क्षेत्र का विकास भी बड़े पैमाने पर किया जाना है इसलिए सभी को इस संबंध में सकारात्मक नीति बनानी होगी। अगले अंक की बात करें तो केंद्र द्वारा नाग नदी के पुनरुद्धार की योजना प्रदान की गयी है। मुला मुठा नदी के संरक्षण के लिए 690 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। हम सभी नदियों को अपनी मां मानते हैं, हम सभी की भावना है कि नदी साफ रहे और उसका पर्यावरण ठीक रहे, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के 2014 मे आने से पहले इसके बारे में न तो सोचा गया और न ही कुछ किया गया। केवल गंगा के लिए ही नही, बल्कि देश के हर जिले की हर नदी के

लिए। मैं पुणे की नदियों के लिए यह फंड उपलब्ध कराने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहती हूं। इसमें सीवेज परियोजनाएँ, रसायनों को नदी में जाने से रोकने की परियोजनाएँ भी शामिल हैं। यहाँ एक बड़ा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जा रहा है जिससे दो लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ग्रामीण सड़क सुधार योजना को सर्व समावेशी विकास के लिए 466 करोड़ रुपये का आर्थिक गलियारा मिला है। प्रधानमंत्री ग्रामसड़क योजना से कितने गांवों को जोड़ा गया है? मेरे महाराष्ट्र में जनता के लिए संचार साधन और कनेक्टिविटी बनाई गई है, 1821 गांवों को जोड़ा जा सका है। विदर्भ मराठवाड़ा कोंकण के कई गांव ऐसे थे जहां पहुंचना मुश्किल था, वहां भी इस ग्राम सड़क योजना के जरिए बड़ी मात्रा में फंड और सड़कें उपलब्ध कराई गईं। कितनी किलोमीटर सड़कें बनीं और कितना फंड मिला, करीब 3933 करोड़ रुपये। मैं शहर में रहती हूं, शहरी विकास मेरा अभ्यास का विषय है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि शहरों में बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाना चाहिए और शहरी संचार सुविधाओं को बढ़ाने के लिए पहल की जानी चाहिए और इसलिए मुख्य रूप से शहरों में स्मार्ट सिटी योजनाएं शुरू की जानी चाहिए। शहरों को अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने के लिए केंद्र से भारी धनराशि प्राप्त हुई है। वहीं, मुंबई मेट्रो कॉरिडोर रीजन के लिए 150 करोड़ का फंड दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए देश भर में तीन लाख घर बनाने का लक्ष्य है। मुझे ये कहते हुए ख़ुशी है कि इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और मेरे महाराष्ट्र के 13 लाख नागरिकों को इसका लाभ मिला है। मुद्रा ऋण योजना से बड़ी संख्या में महिलाओं को लाभ हुआ है। स्टार्टअप के लिए 5 लाख और 10 लाख का फंड कम है। मैं उन्हें बधाई देती हूं और धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने स्टार्टअप के लिए 10 लाख की सीमा पार कर इसे 20 लाख कर दिया, इससे कई लोगों को फायदा होगा। मुझे गर्व है कि 500 नई कंपनियां निवेश कर रही हैं और उनमें से ज्यादातर मेरे महाराष्ट्र में हैं। इसलिए बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन किया जा सकता है। मैं माननीय वित्त मंत्री को एक ऐसी योजना लागू करने के लिए बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूं जो युवाओं को प्रशिक्षण भी प्रदान करेगी। मैं बजट के बारे में ही बात कर रही हूं। महाराष्ट्र की ही बात करें तो महाराष्ट्र में कई लोगों को स्मार्ट सिटी के माध्यम से 11460 करोड़ रुपये का फंड मिला है, रेंटल हाउसिंग के माध्यम से एक बहुत अच्छी योजना लाई गई है, जिससे लोगों को किराये के मकानो के माध्यम से यहां रहने की सुविधा मिल सके । महिला छात्रावास एवं क्रेच के माध्यम से कामकाजी महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मैं एमएसएमई का उल्लेख करना चाहूंगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए.. ...(**व्यवधान**)...

3.00 **P.M.**

THE VICE CHAIRPERSON (SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI): I will have to move on to the next speaker. ...(*Interruptions*)... Please be seated. ...(*Interruptions*)... I request her to please be seated. ...(*Interruptions*)... Please be seated. ...(*Interruptions*)... Sushmitaji, please be seated. ...(*Interruptions*)... Please be seated. ...(*Interruptions*)... Dr. Kulkarni, you have 54 seconds remaining. Either you conclude the speech. ...(*Interruptions*)... You will have to conclude. ...(*Interruptions*)...

Mr. Patel you will have to be seated. ...(*Interruptions*)... Dr. Kulkarni, you continue. ...(*Interruptions*)...

SHRI RAGHAV CHADHA (Punjab): Madam, I have a point of order. ...(*Interruptions*)...

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी : एमएसएमई के माध्यम से महाराष्ट्र के कई उद्योगों और युवाओं को उद्योग और रोजगार प्रदान किया गया है। ...(**व्यवधान**)... मुझे अतिरिक्त समय दिया जाए ...(**व्यवधान**)...

THE VICE CHAIRPERSON (SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI): Dr. Kulkarni, please conclude. I am calling the next speaker. ...(*Interruptions*)... Your time is up. ...(*Interruptions*)... I am sorry. ...(*Interruptions*)...

DR. MEDHA VISHRAM KULKARNI: Madam, please allow me five minutes. ...(*Interruptions*)... I have been disturbed by... ...(*Interruptions*)...

THE VICE CHAIRPERSON (SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI): Now, Shrimati Rajani Ashokrao Patil. ...(*Interruptions*)... Please be seated. ...(*Interruptions*)...

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल : आदरणीय महोदया, ...(**व्यवधान**)...

THE VICE CHAIRPERSON (SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI): Sir, one second. ...(*Interruptions*)... I will call you, Sir. ...(*Interruptions*)...

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल : आदरणीय महोदया, ...(**व्यवधान**)...

डा. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी (उत्तर प्रदेश): मैडम, इनको पाँच मिनट और बोलने दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE CHAIRPERSON (SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI): Five minutes time, okay. Shrimati Rajani Ashokrao Patil, you have to sit down. They are giving her another five minutes. And, I would request you that there can be no further disturbance. There can be no further disturbance from your side. All the disturbance is coming from your side. ...(*Interruptions*)... आप उनसे कहिए कि वे डिस्टर्ब न करें। ...(**व्यवधान**)... No, no. ...(*Interruptions*)... मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर please डिस्टर्ब मत कीजिए, व्यवधान मत डालिए, आपकी ही स्पीकर बोल रही हैं। ...(**व्यवधान**)...

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी : महोदया, अब हम हैल्थ पर बात करेंगे। "एमएसएमई के माध्यम से महाराष्ट्र के कई उद्यमियों और युवाओं को बड़ी मात्रा में धन प्रदान किया गया है। मुझे आश्चर्य है कि इस तरह का डेटा उन लोगों को कौन देता है जो किसी को टीका न लगवाने की बात कर रहे थे। केवल महाराष्ट्र में दस लाख बच्चों को टीका लगाया गया है। एक लाख से अधिक महिलाओं को टीका लगाया जा चुका है। अगर महाराष्ट्र में इतने बड़े पैमाने पर टीकाकरण हुआ है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में कितने बड़े पैमाने पर टीकाकरण हुआ है। पोषण योजना के लिए 1700 करोड़ रुपये, लाभार्थियों की संख्या 68 लाख, विविध आयुष्मान भारत योजना के लिए भी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, शहरी स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से देश को 1532 करोड़ रुपये दिए गए हैं। और ये सिर्फ इस साल का फंड है। अब तक करीब एक लाख, 61 हजार, 88 करोड़ रुपये आरोग्य मिशन के जरिए महाराष्ट्र को दिए जा चुके हैं। एमसी नागपुर में स्थापित है और वहां 160 बिस्तरों वाला अस्पताल शुरू किया जा रहा है, 11000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को वित्त पोषित किया गया है और 587 मेडिसिन केंद्रों को केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है। कोई फंड नहीं, कोई फंड नहीं, पहले स्वास्थ्य योजना से उनकी जांच कराई जाये और उनका पीलिया ठीक किया जाए। **...(व्यवधान)...** इंद्रधनुष योजना के माध्यम से कई महिलाओं का टीकाकरण किया गया है। मुझे आश्चर्य है कि इस तरह का डेटा उन लोगों को कौन देता है जो किसी को टीका न लगवाने की बात कर रहे थे। केवल महाराष्ट्र में दस लाख बच्चों को टीका लगाया गया है। एक लाख से अधिक महिलाओं को टीका लगाया जा चुका है। अगर महाराष्ट्र में इतने बड़े पैमाने पर टीकाकरण हुआ है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में कितने बड़े पैमाने पर टीकाकरण हुआ है। पोषण योजना के लिए 1700 करोड़ रुपये, लाभार्थियों की संख्या 68 लाख, विविध आयुष्मान भारत योजना के लिए धन्यवाद। मैं आपको बड़ी दीदी की फिगर्स बताने जा रही हूं, इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, शहरी स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से देश को 1532 करोड़ रुपये दिए गए हैं। और ये सिर्फ इस साल का फंड है। अब तक करीब एक लाख, 61 हजार, 88 करोड़ रुपये आरोग्य मिशन के जरिए महाराष्ट्र को दिए जा चुके हैं, एमसी नागपुर में स्थापित है और वहां 160 बिस्तरों वाला अस्पताल शुरू किया जा रहा है, 11000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को वित्त पोषित किया गया है और 587 मेडिसिन केंद्रों को केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है। कोई फंड नहीं, कोई फंड नहीं दिया गया, पहले स्वास्थ्य योजना से उनकी जांच करायी जाये और उनका पीलिया ठीक किया जाये। इंद्रधनुष योजना के माध्यम से टीकाकरण और पोषण के माध्यम से पुणे आने वाली स्तनपान कराने वाली माताओं को कई प्रकार की सुविधाएं दी गईं। दस लाख बच्चे लाभार्थी हैं और एक लाख, 24 हजार से अधिक महिलाएं लाभार्थी हैं। पिछले पांच वर्षों में पोषण अभियान के माध्यम से धन का प्रावधान बहुत बढ़ा है और इससे 68 लाख लाभार्थियों को लाभ हुआ है जबकि आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की संख्या 8 लाख है। आइए कृषि क्षेत्र के बारे में बात करें। महाराष्ट्र में कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा प्रावधान किया गया। बलिराजा जलसंजीवनी योजना एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना है जिसके लिए महाराष्ट्र को 30000 करोड़ का सिंचाई फंड मिला है। कृषि क्षेत्र में इतना बड़ा पैकेज अब तक किसी राज्य को नहीं मिला है लेकिन वे इसे नहीं देख पाएंगे क्योंकि उन्हें पीलिया हो गया है। केंद्र सरकार ने ऐसे सूखाग्रस्त

जिलों में सिंचाई परियोजनाओं के लिए 600 करोड़ रुपये का पैकेज दिया है। पर्यावरण अनुकूल कृषि उत्पादों के लिए 598 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं, इस योजना के तहत 170 परियोजनाओं को वित्त पोषित किया गया है और नौ लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई के अंतर्गत आ गया है। चाहे वह कृषि उत्पादक संगठन हों, राष्ट्रीय सहकारी योजनाएँ हों या कृषि अनुसंधान, इन सभी से किसान-प्रधान महाराष्ट्र को लाभ हुआ है। राज्य का 13 प्रतिशत उत्पादन कृषि क्षेत्र पर आधारित है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होकर खेती करने वाले किसान आज आगे बढ़ रहे हैं। 2024 में किसान सम्मान योजना के लाभार्थियों की संख्या 92 लाख 50 हजार है। 2014 से आज तक राज्य को 29 हजार ,959 करोड़ रुपये कृषि क्षेत्र के लिए मिले हैं। ये फंड कम नहीं है। फसल बीमा योजना से मेरे प्रदेश के 1 करोड़ ,14 लाख लोगों को लाभ मिलने वाला है। दीनदयाल कौशल विकास योजना के माध्यम से कई लोगों को लाभ हुआ है। बारह लाख ,86 हजार ,95 लोगों ने इसके माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया है और उन्हें रोजगार भी मिला है। लेकिन वे इसे नहीं देखते क्योंकि वे पीलिया से पीड़ित हैं।" ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल : "जो बूंद से गया ,वह हौद से नहीं आता। आपने बजट में महाराष्ट्र का नाम नहीं लिया और अभी महाराष्ट्र-महाराष्ट्र कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग आपको बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। "

THE VICE CHAIRPERSON (SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI): Now, I have to call the next speaker, Shrimati Rajani Ashokrao Patil.

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल: महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद अदा करती हूं। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE CHAIRPERSON (SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI): Yes, I will call him after this. I had already called out her name. I had called out his name two times, he was not present in the Chamber. I have called out her name; let her conclude her speech and I will be happy to hear his maiden speech.

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल * "मै आपका शुक्रिया अदा करती हूं। राज्य सभा में मेरी नव-निर्वाचित सहयोगी मेधा ताई कुलकुर्णी का भाषण मैंने गौर से सुना और मेरी समझ में आया कि उनको इतना बोलने के लिए क्यों प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसका एकमात्र कारण है महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव, और वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में महाराष्ट्र के 'म' का भी उच्चारण नहीं किया। तो ये बूंद से गई वो हौद से नहीं आती वाली बात हो गई। महाराष्ट्र का नाम भी आपने भाषण में नहीं लिया। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि मैं आज मराठी में भाषण देने वाली हूं क्योंकि मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए ,ऐसी मांग हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बार

* Hindi translation of the the original speech delivered in Marathi.

की है, लेकिन इस सरकार ने पिछले 10 सालों में मराठी को शास्त्रीय भाषा का सम्मान देने का प्रयास भी नहीं किया। इसलिए मैं मेरी प्राचीन भाषा, जो मराठी है, उसमें आज बोलने वाली हूं। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अभिनंदन करती हूं क्योंकि वे एक महिला हैं, महिला मंत्री हैं और हमारे देश का छठा बजट उन्होंने पेश किया है, इसलिए महिला होने के नाते मुझे उन पर अभिमान है।

महोदया, इसलिए भी मुझे अभिमान है कि हमारे चुनाव घोषणा-पत्र के बहुत से मुद्दों को कॉपी-पेस्ट करके इस बजट में लिया गया है। पहली नौकरी पक्की, यह मुद्दा हमारे घोषणा-पत्र में है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 4 हजार किलोमीटर की यात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक वे पैदल चलते गए और बीच में जो भी मिले, चाहे वे जवान हों, बूढ़े हों, किसान हों, उन सबसे वे मिले और उनको कहा कि आपकी जो समस्याएं हैं, उन पर ध्यान खींचने का काम मैं करूंगा और इस तरह हमारा घोषणा-पत्र तैयार करने का काम राहुल जी ने किया। 25 साल तक के बच्चों को हम नौकरी देंगे, ऐसा उसमें कहा गया है। और इन्होने पहली नौकरी पक्की करने का मुद्दा इस बजट में लिया, वह उनको पक्का ध्यान में रहा। ऐसा कहा जाता है कि जब आप किसी की नकल उतारते हो तब आप उसकी प्रंशसा करते हो, इसलिए मैं उनके इस नकल करने का स्वागत करती हूं।

महोदया, भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने कल एक साक्षात्कार दिया। लोक सभा चुनावों के बाद निर्मला सीतारमण जी को पहला बजट पेश करने का अवसर मिला और उन्होंने उसमें हमारी कुछ कल्पनाएं स्वीकार कीं। उसमें रोजगार पाने के लिए इन्टर्नशिप करते समय स्टाईपेंड देना और ऐंजल टैक्स रद्द करना, ये हमारी कुछ प्रमुख मांगें थीं और उन्होंने वह स्वीकार की, लेकिन इनको अपने घर से ही उत्तर मिल गया क्योकि अनंत नागेश्वर राव ने इकोनोमिक सर्वे के बारे में कहा है कि सिर्फ 51 प्रतिशत पात्र युवकों को ही नौकरियां मिल सकती हैं। मेधा ताई ने यहां सवाल उठाया कि युवाओं को विधायक निवास तक जाने की क्या जरूरत है, तो ये युवा विधायकों के घरों तक जाते हैं क्योकि उनको कहीं नौकरियां मिलती नहीं हैं, वे बेबस हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदया, स्वतंत्रता के बाद देश मे कई वित्त मंत्री हुए। पहले वित्त मंत्री लियाकत अली खान से लेकर सी.डी. देशमुख, जोन मथाई, कृष्णन्मचारी, यशवंतराव चव्हाण, यशवंत सिन्हा, प्रणब मुखर्जी, डॉ. मनमोहन सिंह, पी. चिदम्बरम, अरुण जेटली, ऐसे बड़े-बड़े वित्त मंत्री हुए और उन्होंने देश को आगे ले जाने का प्रयास किया। 24 जुलाई, 1991 का दिन हमें ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि 33 साल पहले 24 जुलाई, 1991 को देश का ऐसा पहला बजट डॉ. मनमोहन सिंह जी ने पेश किया था जो क्रांतिकारी था और देश को एक नई दिशा देने वाला था। डॉ. मनमोहन सिंह के दूरगामी नेतृत्व में देश को औद्योगिक क्रांति की एक नई राह मिली, हमें यह मानना पड़ेगा। Continuity with Change, यह उनकी मूल कल्पना थी और आज तक वही चलती आ रही है। मेरी वित्त मंत्री से विनती है कि उन्हें सब राजनैतिक पूर्वाग्रहों को दूर रखकर कांग्रेस, इंडिया के सदस्य, देश के बुद्धिजीवी, अर्थशास्त्री इन सबकी राय अपने बजट के संदर्भ में लेनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है।

बेरोजगारी के बारे में मुझे कहना है कि अभी जो भाषण हुआ, वह सुनते समय मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हम राज्य की विधान सभा में है या राज्य सभा में क्योंकि राज्य सभा में देश की समस्याएं रखनी चाहिए। मेरा ताई को सुझाव है कि आपकी पार्टी ने आपको कहा होगा कि चुनाव

आ रहे हैं लेकिन चुनाव आये हैं तो महाराष्ट्र का नाम भी भाषण में लेना चाहिए था। महाराष्ट्र का नाम भी आप ले न सके। बेरोजगारी का एक उदाहरण देती हूं। मेरे बीड जिले में पुलिस भर्ती थी, गरीब घरों के बच्चे ग्रामीण इलाकों से जिले मुख्यालय तक बीड पहुंचे थे। जब वे पहुंचे तो बहुत से बच्चों के पास खाने को भी पैसे नहीं बचे थे। किसी के पास बस के किराये के पैसे नहीं थे और जब शारीरिक क्षमता परीक्षा के लिए उनको दौड़ने के लिए कहा गया तो उनमें से बहुत सारे चक्कर खाकर गिर गये। एक-दो बच्चों की मृत्यु भी हो गई। उनको यही दिख रहा था कि मैं आज यहा दौड़ा तो ही मुझे नौकरी मिल सकती है. तो बेराजगारी के बारे में अच्छे चित्र दिखाने से कुछ नहीं होगा, **झूठ** न बोलें। कुछ जगहों के लिए लाखों में अर्जियां आती हैं। सी.एम.आई.सी. के अनुसार देश में बेरोजगारी का आकड़ा 9.2 प्रतिशत है। होलसम प्राईस इंडेक्स 3.4 प्रतिशत, कंज्यूमर प्राईस इंडेक्स 5.1 प्रतिशत और फूड इंन्फलेशन 9.4 प्रतिशत है.

इन सब आकड़ों के जाल में न फंसते हुए सामान्य महिला की भाषा मे कहा जाए तो आज सब सब्जियों के दाम डबल डिजिट मे चले गए हैं। टमाटर के दाम तीन डिजिट के पार गए हैं। यह हम सब सामान्य लोगों की स्थिति है। विश्व बाज़ार मे कच्चा तेल कितना भी सस्ता हुआ फिर भी हमारा डीजल, पेट्रोल, गैस सस्ता होने का नाम नहीं लेता। हमारी महिलाएं अष्टभुजा होती हैं। हम अष्टभुजा देवी की पूजा करते हैं। महिला भी अष्टभुजा होती है, वह एक हाथ से खाना बनाती है, एक हाथ से बच्चों को देखती है, एक हाथ से पति की सेवा करती है, कोई यहां आके भाषण भी देती है, ये हम सब करते है। कामकाजी महिलाओं के लिए शहरों मे होस्टल की कल्पना अच्छी है, लेकिन ऐसे कितने होस्टल आपको बनवाने पड़ेंगे? देश की जनसंख्या कितनी है? तो इसलिए जब तक महिला आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं होती तब तक वह स्वतंत्र है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। इसलिए महिला आरक्षण एक अलग विषय है। मेरे बगल में महिला विभाग की भूतपूर्व बैठी है. उनके समय देश मे महिला बचत गुटों का जाल तैयार हुआ था। मैं खुद केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, महिला आर्थिक विकास बोर्ड की अध्यक्ष थी, उस समय हमने बहुत महिलाओं को बचत गुटों के माध्यम से एक साथ लाया, बचत गुटों में महिलाओं को घर, बच्चे संभालते हुए काम करना, आसान होता है। इसलिए हमने ऐसा काम किया तो महिलाएं स्वावलंबी हो जाएगी, ऐसा मेरा सुझाव है, आप उस पर जरूर विचार करें।

आज नारी शक्ति वंदन अभियान शुरू है। ये इतने कठिन नाम रखते हैं, ये नारी शक्ति को वंदन करते हैं लेकिन नारी को पूछते नहीं हैं। आज राजीव गांधी जी की दूरदृष्टि के कारण हमको आरक्षण मिला है। पंचायत से लेकर जिला परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका इनमे हमारी जैसी महिलाएं चुनकर आई, वह सिर्फ राजीव गांधी जी ने महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया इसलिए और इसके बाद हमने जब लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा, विधान परिषद इनमे आरक्षण मांगा तब वो हमे मिल न सका। उसके लिए बहुत सालों की प्रतीक्षा करनी पड़ी। पिछली बार जब हमने सबसे पहले इस नए सदन मे प्रवेश किया तब मोदी जी ने ढोल-नगाड़े बजाते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो गया लेकिन ये आरक्षण हमे कब मिलेगा? तो 2029 मे! और वो भी जनगंणना हुई तो संभव है. इसका मतलब यह बात बीरबल की खिचड़ी की तरह है जो कब पकेगी कहा नही जा सकता. आप आज चर्चा करते हो और फिर कहते हो कि यह बाद मे होगा, मुझे लगता है कि उसके लिए जातीय जनगंणना जल्द-जल्द से करनी चाहिए.

किसानों के बारे मे यहां बात करनी चाहिए मै खुद किसान कि बेटी हूं. इसलिए बुआई, सिचांई, कटाई ये सब काम मैने किए है सिर्फ मै उस पर भाषण नही देती हूं। किसान को सही गारंटी देनी है तो बड़े-बड़े शब्द या नामों का इस्तेमाल करके कोई फायदा नही. इस बजट मे सरकार ने किसानों को कुछ नही दिया है, देश ने 58 प्रतिशत से ज्यादा किसान परिवार है उनमे भी 85 प्रतिशत परिवार अल्पभूधारक है उनके पास कम ज़मीन है। आज किसान बहुत अस्वस्थ है। कल ही किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल पंजाब और हरियाणा से आया था. हमारे नेता राहुल गांधी जी को वो मिले और उन्होने अपनी समस्याएं बताईं, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा ये कृषि-प्रधान राज्य है. दुर्भाग्य से मेरा महाराष्ट्र किसानों की आत्महत्याओं के लिए जाना जाता है। आज सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या महाराष्ट्र मे होती है। 2022 मे 37.60 प्रतिशत किसानों ने आत्महत्याएं की। अमरावती जिले मे पिछले 6 महीनों में 618 किसानों आत्महत्या की। दो साल पहले पंजाब और हरियाणा के किसान अपनी न्याय्य मांगों के लिए, लड़ने के लिए यहां आये तो इन्ही लोगों ने उनको आंतकवादी ठहराया और आज ये किसानों के लिए रोना रो रहे है। इसी देश मे 786 किसान शहीद हुए। आजाद भारत मे किसान शहीद होते है, ये कितना बड़ा विरोधाभास है, दुर्भाग्य है! मोदी जी ने आश्वासन दिया था कि 2022 मे किसानों की आय दुगनी करेगे, 2024 आ गया अभी कुछ नही हुआ। एम.एस.पी. का कानून कीजिए ऐसी हमारी मांग है। आप स्वामीनाथन को भारतरत्न देते हो लेकिन उन्होने जो कहां वो मानते नही हो। उनकी सूचना के अनुसार किसान को न्यूनतम मूल्य के 50 प्रतिशत ज्यादा ये जब तक अमल मे नही आता तब तक हमारा किसान सुखी नही होगा। ये वास्तव है और वही परिस्थिति सामने रखने के लिए लोगों ने हमें यहां भेजा है। मुझे याद है यू.पी.ए. के समय हमने 72 हजार करोड़ रूपयों का किसान कर्जा माफ किया था लेकिन आपने उर्वरक, इंधन का अनुदान भी घटा दिया। मतलब बजट मे आपने किसानों को कुछ भी नही दिया। आपने कृषि-उत्पादों की निर्यात बंदी की। आज नासिक जिले मे इसी निर्याद बंदी के कारण प्याज रास्ते मे फेकना पड़ा और किसानो का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये विडंबना है। मेरे मराठवाड़ा मे सोयाबीन का उत्पादन होता है। आप सोयाबीन विदेश से मंगवाते हो। जो सोयाबीन 3 साल पहले 7,500 से 8 हजार रूपये था, वही आज 3 हजार मे बेचना पड़ रहा है.

हमने मनरेगा योजना लाई थी। हमारे यू.पी.ए. के समय वो बहुत बड़ी योजना थी। दुर्भाग्य से नरेन्द्र मोदी साहब ने उसका मजाक उड़ाया और एक बार मै राज्य सभा मे थी तब उन्होने कहा कि मै यह योजना रद्द नही करूगा तो कांग्रेस की विफलता का उदाहरण करके लोगों को दिखाऊगा लेकिन उनका ही दुर्भाग्य देखिये कि कोरोना समय यही विफलता काम आई और लोगों को उससे जीवन मिला। यह उनका दुर्भाग्य है लेकिन हमारा अच्छा काम मुझे लगता है कि मनरेगा का जो बजट है वो बढ़ाना चाहिए क्योकि अभी भी महाराष्ट्र या देश के अन्य भागों मे कही बाढ़ है तो कही अकाल है, उन गरीबों को सहारा देने के लिए हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा।

महाराष्ट्र मे बहुत बड़ा अंसतोष है, आप उसकी तरफ कैसा देखते है मुझे पता नही लेकिन हम दिल्ली से जो देखते है उसके विपरीत महाराष्ट्र मे बहुत बड़ा अंसतोष है। ग्रामीण इलाकों मे किसानों के बच्चे रास्ते मे आकर न्याय मांग रहे है। हमारे मराठवाड़ा मे मनोज जरांगे पाटिल ने आंदोलन खड़ा किया और कल ही उनका अनशन खत्म हुआ। मराठा, धनगर, मुस्लिम इन समाजों को न्याय मिले इसलिए वे आंदोलन कर रहे है। वो न्याय दिलाने का काम हमे करना चाहिए। इसमें पार्टी के भेद नही आने चाहिए उनको न्याय देने का काम हमे करना चाहिए और सभी वर्गों का

न्याय मिले ऐसा प्रयास हम सभी को करना चाहिए। राहुल जी ने कास्ट सेंसस की मांग की है उनका कहना है की कास्ट सेंसस से ही हमे पता चलेगा कि किस जाति के कितने लोग है और उनको न्याय देना आसान होगा। सेंसस के लिए इस बजट मे कोई प्रावधान नही है। जब सेंसस ही नही होगा तो महाराष्ट्र मे और देश मे जो अभी भी 12-13 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर है उनको हम कैसे मदद कर सकेगे जिनको हम खाद्य सुरक्षा बिल मे नही ले सकते, इसलिए सामाजिक-आर्थिक यानी socio-economic census यह बहुत जरूरी बात है।

मैडम, आप मुम्बई से हो इसलिए आपको पता होगा कि देश की अर्थव्यवस्था मे महाराष्ट्र की भूमिका बहुत बड़ी है. मुम्बई देश की आर्थिक राजधानी है. देश के कुल कारपोरेट टैक्स मे 40 प्रतिशत, आयकर 32 प्रतिशत और 20 प्रतिशत जी.एस.टी. - ये महाराष्ट्र से देश को मिलता है, दिल्ली को मिलता है और दिल्ली हमको क्या देती है, एक रूपये मे से सिर्फ 7 पैसे! आप बड़ी-बड़ी बात करते हो तो इस बात पर भी सोचना चाहिए. Creative Redevelopment of Urban Land Spaces इसका जिक्र निर्मला जी ने किया लेकिन इस योजना मे धारावी है क्या? धारावी, यह मुम्बई का बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर धारावी मे आप Creative Redevelopment करते हो और धारावी का पुनर्विकास का काम एक बड़े उद्योगपति को दिया गया है ऐसा हमने सुना। मै स्पष्ट नाम लेकर कहती हूं कि यह काम अडाणी को दिया गया है, तब तो देश का दुर्भाग्य है कि मुम्बई जैसे महानगर मे आपने इतनी बड़ी जगह एक उद्योगपति को दे दी। यह देश कहां जायेगा यह पूछना पड़ेगा और फिर उन्होनें कुर्ला, मुलुंड और खार सोफ्ट पेन लैंड इनकी भी मांग की है। मुझे लगता है कि इस पर सरकार का स्पष्टीकरण आना चाहिए. महाराष्ट्र के बहुत सारे उद्योग पिछले 10 सालों मे बाहर गये है, दूसरे राज्य मे गये है। ...(**व्यवधान**)... और हीरा उद्योग सूरत को गया है । गुजरात मे इसी तरह टाटा एयरबस और वेदांत जैसे बड़े उद्योग भी गुजरात को गए है. फैक्सोन तथा वस्त्र उद्योग यह सब महाराष्ट्र के बाहर ले जाकर आपने महाराष्ट्र पर जानबूझकर अन्याय किया है। इन्होनें 2014 मे कहा था कि कहां लेकर रखा मेरा महाराष्ट्र? हम आपको पूछते है भूपेश जी कहां लेकर रख दिया मेरा महाराष्ट्र? इस पूरे बजट मे महाराष्ट्र के साथ-साथ छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखण्ड, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडू, केरल पश्चिम बंगाल इन सब राज्यों के प्रति सौतेला व्यवहार किया गया है। महाराष्ट्र का तो नाम तक नही लिया गया। जो राज्य आपको इतना पैसा देता है उस पर आपने इतना बड़ा अन्याय किया, क्यों ? तो वहां से आपको वोट नही मिले। राजनीति के पार जाके संघ-राज्य रचना का विचार करना चाहिए और सभी राज्यों को साथ लेकर महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, सभी को साथ लेकर चलना चाहिए - मुझे ऐसा लगता है। लेकिन दो राज्यों को बजट मे भर-भर के दिया गया है। हम दो हमारे दो। बिहार और आंध्र प्रदेश पर इनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। 3 एन-निर्मला, नायडू और नीतीश बाबू. और इसलिए इन दोनों को बहुत मिला है। हम पहले कहानी सुनते थे तो किसी राजा को एक रानी प्रिय होती है और दूसरी अप्रिय, तो हम सब अप्रिय हो गए हैं और प्रिय रानियां दो ही हैं, वे हैं - आंध्र प्रदेश और बिहार।

अगर विद्यार्थियों के बारे मे न बोलूं तो अन्याय होगा। नीट और यू.जी.सी. नीट पेपरलीक की खबरें सामान्य परिवार से आये हुए बच्चों को उधवस्त करने वाली हैं। जब लोग गड़बड़ी करके आई.ए.एस. की कुर्सी पर जाकर बैठते हैं तो रातदिन मेहनत करने वाले सामान्य घर के बच्चों को कितना दुख होता होगा। इसमे यू.पी.एस.सी. के अध्यक्ष ने जो इस्तीफा दिया उसका स्वागत है।

Ceasar's wife must be above suspension. आरोग्य सुविधा के बारे मे मुझे दो बातें कहनी हैं। ये आयुष्मान भारत नही तो उधवस्त भारत बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किसी भी देश की जी.डी.पी. के 5 प्रतिशत खर्चा आरोग्य पर होना चाहिए। हमारे देश मे ये प्रमाण 1.9 प्रतिशत है सिर्फ। पिछली बार भी मैंने राज्य सभा मे कहा था कि हमारे देश मे आरोग्य सुविधाओं की स्थिति अच्छी नही है, इसमें भी सुधार लाना होगा। आरोग्य सुविधाओं के बारे में मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड जैसे देश भी हमसे आगे निकल गये हैं। इसके अलावा डायबिटिज और बी.पी. से ग्रस्त लोगों की संख्या हमारे यहां हर 10 मे से 7 इतनी बड़ी है। इसकी दवाई पर उत्पादन शुल्क घटाना चाहिए, इससे लोगों को राहत मिलेगी।

विकसित भारत का नारा देने वाली इस सरकार ने लोगों को कितना प्रताड़ित किया है, सिर्फ नारे दिये जाते हैं विकसित भारत, स्टैंड-अप इंडिया, 400 पार ये सब नारे सिर्फ जुमले हैं और कुछ नही। तो विकसित भारत का नारा देने वालो ने हमें कितना भी प्रताड़ित किया, हम 145 सांसदों को निलंबित किया गया और बिल पास करा लिया गए। आपका भी निलंबन हुआ था तो हमने यह तय किया है कि हम भी टूटेंगे नही, कपिल सिब्बल जी ने बताया था "*शाखों से टूट जायें वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि वो औकात मे रहे।*"

धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।"

THE VICE CHAIRPERSON (SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI): Thank you. Just one observation -- I may be your junior, the person sitting on the Chair may be your junior, and you all may be more experienced, but when someone is sitting on the Chair, that person should not be disrespected because that is disrespect of the Chair. It is an observation. I would like to call Shri C.Ve. Shanmugam, who will be making his maiden speech.

SHRI C. VE. SHANMUGAM (Tamil Nadu): Madam Vice-Chairman, I pray to my eternal leader, *Amma*, am thankful to our Party General Secretary, Shri Edappadi Palanisamy, and thank you for the opportunity to speak on the Budget 2024-25 presented by the hon. Finance Minister. There are several issues that have not been adequately addressed in the Budget. I request the hon. Finance Minister to consider them for allocation of funds to Tamil Nadu. Tamil Nadu has been receiving secondary treatment from the Central Government in terms of budgetary allocation and programme implementation. No new projects have been initiated in Tamil Nadu. Only the existing projects have been revamped for upgradation and modernization, which have often been superficial. Between 2009-10 and 2023-24, Rs. 36.6 lakh crore was collected by the Union Government as cess and surcharge. An additional Rs. 5.5. lakh crore is projected for 2024-25. This amount was not shared with States and was used solely by the Union Government. The Finance Minister mentioned simplifying and rationalizing the tax structure to multiply the benefits of GST. Tamil

Nadu, a fast developing industrial State, faces severe hardships due to GST, which needs to be addressed.

As our former Chief Minister and General Secretary of AIADMK, Shri Edappadi Palanisamy stated, even though the Hosur-Coimbatore Defence Corridor was announced, no allocation of funds was made for this project. Lack of funding delays development and operationalization, hindering potential economic benefits and job creation. Tamil Nadu requires substantial investment to develop infrastructure due to rapid urbanization and industrial growth. The budget allocation for infrastructure projects is insufficient, hindering economic growth and job creation. Without adequate infrastructure, industries cannot thrive and citizens cannot access opportunities. While phase-I of the Chennai Metro rail project has been completed, phase-II requires substantial funding to continue expansion and meet projected deadlines. The lack of financial support is slowing progress. The Salem-Chennai eight-lane express highway aims to enhance connectivity, facilitate faster movement of goods and people and promote economic growth. The project requires necessary funding and support to overcome current challenges. The Ministry claims to have completed 76 projects in Tamil Nadu, but most of these are pre-existing projects that have been given a facelift. The real benefactors are the contractors, not the public. Talking about flood mitigation, there is no mention or allocation of funds for flood mitigation measures despite Tamil Nadu frequently facing cyclones. Coming to employment-linked incentive schemes, three schemes as part of the Prime Minister's package to boost employment and growth of the MSME sectors have been announced. As for interlinking of Godavari and Cauvery rivers, there is no mention in the Budget despite its importance for the farmers. The Centre should devise schemes to prevent the youth from taking drugs and liquor concerning the recent tragic incident in Tamil Nadu where the consumption of spurious liquor led to 70 deaths. The allocation of funds in the Budget for 2025 does not sufficiently address the pressing needs of Tamil Nadu in infrastructure, social justice, healthcare and education. Tamil Nadu needs projects and funds, not the *halwa* made pre-Budget.

SHRI SAMIRUL ISLAM (West Bengal): Madam, to say in one sentence, this Budget is anti-people, anti-poor and anti-Bengali. This is the Budget that deprived Bengal of Rs. 1,71,000 crore, which is pending from the Union Government. But it didn't say a single word about it. In this Budget, we have seen how it has become a budget for Bihar and Andhra Pradesh. It is not the Union Budget; it is a Budget to satisfy the ally constituents to save the Government only. We don't have any problem if the Union Government gives something to other States, but why have they deprived Bengal?

(THE VICE CHAIRMAN (SHRI VIVEK K. TANKHA) *in the Chair.)*

It is painful to see how this Budget has ignored the under-privileged in our country, especially those in the unorganised sectors. They are neglected in this Budget. This Budget has failed to address the needs of the unorganised sector workers who are 43.39 crore, according to the Economic Survey 2021-22. Sir, 83 per cent of India's workforce is employed in unorganised sector and my concern lies here. The Government often doubts the registration of workers on the e-SHRAM portal and Pradhan Mantri Yojana to deflect criticism from Opposition Members of this august House. However, the Government's action repeatedly has demonstrated lack of concern for unorganised sector workers. Just before the Budget was presented, the Supreme Court criticised the delay in verifying migrant workers registration on the e-SHRAM portal for the issuance of ration cards. I would like to know when this task would reach a substantial stage. It is disheartening that the Court had to remind us about the plight of migrant workers who are a vital part of the unorganised sector. Government's own NSO Report has revealed that unincorporated enterprises in the manufacturing sector lost some 5.4 million jobs from the middle of 2015-16 to 2022-23 and that 1.8 million establishments were lost. In contrast, West Bengal is the only State to have established a Migrant Workers' Welfare Board under the leadership of our hon. Chief Minister, Mamata Banerjee, dedicated to the development of those who toil with honesty. My demand is simple and clear. Why couldn't the Union Government announce a similar National Migrant Workers' Welfare Board for the migrant workers in this Budget? Hundreds of migrant workers die in workplace accidents or during their travels, yet this Budget has failed to announce a comprehensive insurance scheme to support their families. At a time when inflation is a major issue and a constraint for the survival of the poor, the Government should have announced a project to aid migrant workers in child education and healthcare. According to the Census data of 2011, Uttar Pradesh and Bihar have the highest number of migrant workers, with a combined total of approximately 239 million workers. However, the Union Government, currently, lacks accurate data on the number of migrant workers. The Ministry of Labour and Employment initiated a nationwide review of migrant workers on April 4, 2021. The grim reality of migrant workers became painful during the unprecedented Covid-19 pandemic outbreak. The Finance Minister proclaimed about linking the *eShram* portal to other portals for workers and labourers to facilitate them in availing different services. I wonder if the Finance Minister, or her colleagues in the Cabinet, has ever spoken to any of the

migrant workers. When we feel proud of this new Parliament Building, इस बिल्डिंग में भी बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स का भी हिस्सा है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कहता हूँ कि आप लोग उन माइग्रेंट वर्कर्स के लिए कुछ कीजिए and try to understand whether registering on eShram has given them the benefit of even a single rupee so far. The Finance Minister announced rental housing with dormitory type accommodation for industrial workers in PPP mode with VGF supportyet the ARHC scheme launched by the Union Government in the aftermath of Covid-19 for migrant workers in cities has failed miserably and has not found any takers from the private sector. This is only lip service and just an eye wash.

Apart from the migrant workers, crores of people are involved in unorganized sector, agriculture and the MSME sector. After the Budget, the Prime Minister, Shri Narendra Modi, said that this Budget would help in propsering the MSME sector. Unfortunately, this Government did not favour those small, medium and micro entrepreneurs. This Government has systematically ruined the MSME sector during the past ten years under Narendra Modi regime. I am proud to come from Bengal, which, in the last ten years, has always been in the top 10 States in MSME sectors. This Government imposed a burden of GST on the MSME sector and disbursement methods have been so designed as to discourage medium, small and micro level investors. In this Budget, we did not see any announcement to promote the MSME sector. When unemployment became the prime constraint of development in PM Modi's regime, the systematic destruction of the MSME sector ensured another step to worsen the problem of unemployment.

It is vital to reiterate that not only migrant workers, but this Budget also failed to outline any benefit for tribal people, *dalits*, SCs and minority communities. Recently, a BJP MLA in Bengal, the LoP, suggested abandoning the PM's slogan, "सबका साथ, सबका विकास" and replacing it with "जो हमारे साथ, हम उनके साथ।" This is the real face of BJP. ...*(Interruptions)*...

THE VICE CHAIRMAN (SHRI VIVEK K. TANKHA): Let him speak, please. ...*(Interruptions)*... He has a right to speak.

SHRI SAMIRUL ISLAM: He has revealed the hidden agenda of the Government, which aims at undermining India's fabric, depriving minorities, SCs, STs, dalits and all the marginalized sections of the society in our country. ...*(Interruptions)*... This Budget did not announce anything related to welfare of the minority communities. ...*(Interruptions)*... I urge the Government to introduce a fresh and new scheme for minority communities. The Finance Minister did not utter a single word on minority

welfare in her speech, nor has she announced any special measure for education, skilling, employment or livelihood of minority communities. ...*(Interruptions)*...

THE VICE CHAIRMAN (SHRI VIVEK K. TANKHA): Let him speak, please. ...*(Interruptions)*... It is his right to speak.

SHRI SAMIRUL ISLAM: The Budget allocation for the pre-matric scholarship has been reduced from Rs.400 crores to Rs.326 crores. Over the last few years, the Union Government's only focus is to change the names of the Central schemes of the Ministry of Tribal Affairs. After the *Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana*, this time, the Finance Minister has announced the launch the *Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan*. I want to ask the Union Government as to what has been the outcome of the previous schemes which meant for the tribal welfare.

Surely, your colleagues in Madhya Pradesh have shown the way and diverted crores of rupees of Government funds meant for tribal welfare to construction of cowsheds and *gaushalas*. Sir, I am a young Indian of 37 years living in Bengal. I am absolutely sure that our great nation will keep the divisive and destructive forces out, just like what we did on June 4, 2024. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI VIVEK K. TANKHA): Next speaker is Shri M. Mohamed Abdulla.

SHRI M. MOHAMED ABDULLA (Tamil Nadu): Sir, I rise to oppose the Union Budget, 2024-25. Sir, I hope you have heard about the word *'karma'*. *Karma* is what you sow is what you reap. What you give, you will get; what you do, you will have. They always thought about minorities in a negative way, and, they ended up being a minority Government. That is karma. Yes, what you sow is what you reap.

Sir, before I begin to point out three key failures of the Budget, I would like to thank the Indian people for putting BJP in its rightful place in the august temple of democracy. Hon. Finance Minister has become the first Finance Minister to present the Budget for seven times in a row. I congratulate her on her achievement of delivering these Budget speeches in a row, but the people of the country, especially, the middle class, feel that she has failed miserably for the seventh time without getting the pass marks. We expected good economic reforms and people-oriented schemes from her but she has betrayed our hopes.

Sir, this Government is newly married to Bihar and Andhra Pradesh. We know very well that all the grooms spend lavishly for the newly-married wife only in the

beginning and not all the time. On the day of the marriage itself, everyone in the country knew that they will get divorced very soon. In America, at times, people get married for getting 'green card'. Everyone knows that it is not a real marriage and they marry only to get that 'green card'. It is called a marriage of convenience. Similarly, it is a Budget of convenience. We are waiting to see if the two States will run away after taking the 'special packages' or these people will run away after taking their Members of Parliament. We are waiting to see this.

When the hon. Prime Minister talks about *'vikas'*, we should not interpret it as growth, harmony and peace for ourselves and India. It must be translated as unimaginable growth for his beloved Gujarati 2A businessman friends. Prime Minister said, *'Sabka Saath, Sabka Vikas' but that 'saath and vikas'* is meant for only two people and not the whole of India.

Hon. Vice-Chairman, Sir, in the Interim Budget, 2024-25, the Finance Minister claimed to have lifted 25 crore people from multi-dimensional poverty above the poverty line. Among these 25 crore people, I know only two people, the 2A businessmen. Who are the other 24,99,99,998 people? Sir, why is the Union Government favouring some States and harming revenue-generating States like Tamil Nadu? Ignoring Opposition demands with such bias betrays our democracy and the cooperative federalism in our Constitution. Why is this bias? Why is this hypocrisy? It is very sad that the Union Government which is supposed to represent the people of the country as a whole is a puppet of very few. The Budget, 2024 has provoked constructive debate and unbearable disappointment in Tamil Nadu, a State known for its robust economic contributions and industrial prowess. Tamil Nadu, often regarded as the manufacturing hub of India and a key player in sectors like automobiles, information technology and textiles, expected substantial support and recognition in this year's budgetary allocations, but it received nothing but disappointment. Even though issues like flood relief fund and pending GST compensation have emphasized the demands of Tamil Nadu, the Union Budget has not addressed any of these pressing demands.

Sir, it is very unfortunate and unfair to see the Union Government's unequal distribution of income to the State Governments, especially for non-BJP ruled States like Tamil Nadu, which provides the highest tax for the Union Government. For instance, out of the disaster relief of Rs. 37,906 crore, demanded by the Government of Tamil Nadu for being severely affected by floods in 2023, a paltry sum of Rs. 276 crore only was given by the Union Government. The Union Government has provided approximately Rs. 4.75 lakh crore to Tamil Nadu from 2014-15 to 2022-23, while the direct tax collection from the State during this period was approximately Rs. 6.5 lakh

crore. Sectors pivotal to Tamil Nadu's economy, such as agriculture, education and healthcare have not received the support needed to foster sustainable growth and development. The Finance Minister, who spoke about the nation's food security, while allocating funds for the Polavaram Project in Andhra Pradesh, has conveniently forgotten the farmers of the Delta region of Tamil Nadu, who are equally important for the food security of the country. Our Finance Minister has brought up and graduated in Delta region only.

The Education Ministry, UGC and NTA have lost the trust of the people due to continuous scams. The Director General of NTA has resigned and ran away; the UPSC Chairman has resigned and ran away from his responsibilities. But the Union Minister for education is giving sermons as if nothing happened in NEET question paper leak. As an MP from Tamil Nadu, our long-held stand is NEET is not needed and all common entrance exams conducted by the Union Government must be stopped. For a true federal arrangement, the exams must be run by all the State Governments, duly voted by their own people and move higher education back to the State List. By tinkering with education, we are not only failing our future generations, but also shaking the fundamentals of this unified country.

The Union Government has also stopped the payment of around Rs. 2,000 crore to the Government of Tamil Nadu under Sarva Shiksha Abhiyan only because we do not agree with the New Education Policy which I imposes Hindi and is against our State autonomy.

When this Government came to power for the first time, our hon. Prime Minister proclaimed that they would create 20 million jobs annually. The Economic Survey, 2024 says that 8 million jobs need to be created till 2036. This Government has the habit of hiding uncomfortable data from the public eye. This Government does not respect any international data, while none of the data delivered by this Government is respected in global circles. This means we only have a self-delusional leader, and the entire Cabinet, supporters, social media, TV channels are singing his paeans without focusing on the people. I am reminded of the emperor Nero, who was busy with his fiddle while Rome was burning. The unprecedented unemployment problem in the country is getting worse day by day and the Government's failure to tackle the unemployment problem in the country is unpardonable. Unemployment rate is at its highest in independent India and if you see, the unprecedented crowd of youth from north India in the south-bound trains is an ample proof for this unemployment problem in the country. I am satisfied with the fact that this minority Government did not announce that they would provide jobs to 40 crore youth from across the whole world.

The Indian Railways, typically a central focus in the Indian Budget and a major recipient of funds, surprisingly did not receive attention in the Budget of 2024 even after consecutive train accidents.

While the Union Budget of 2024 sets the road map for India's economic path, its reception in Tamil Nadu underscores the necessity for inclusive and region-sensitive policy-making. Addressing the concerns of States like Tamil Nadu is not just about financial allocations. It is also about fostering a sense of equitable growth and partnership in India's journey towards prosperity.

I want to say something in Tamil. I will translate it also. Banks are harassing people by levying interest on interest whereas the Union Government is extracting tax on taxes from the people. Only two kinds of people can live comfortably in this country. One is super rich. Second one is hon. children of *paramaatma*. Whether any concrete steps are being taken by the Government to review the Union Government and State Government relations to uphold cooperative federalism in this Budget. The answer is 'No'.

There are four things that our Dravidian model Government in Tamil Nadu has given to Indian politics which is mandate now for the development of this country. First is equality. Second is social justice. Third one is State autonomy. And the fourth one is welfare economics. All these were shaped by the unique historical continuity of Tamil Nadu on the basis of social justice guided by Thanthai Periyar, Perarignar Anna, Muthamil Arignar Dr. Kalaignar and now by our hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Thalapathy M.K. Stalin. This minority Government should understand this first.

Sir, before I conclude my speech, I would like to strongly register my protest against what the BJP leaders said during the campaign trail about minorities. My name is Mohamed Abdulla. My mother tongue is Tamil. I am a Tamil-speaking Muslim. For generations, we follow Islam. My floor leader, hon. Siva Anna, told this in this august House not once but many times. He said this outside on stages also. During the partition, we had a choice, but my forefathers stayed back. Siva Anna told this earlier in this House. Muslims had a choice. But their forefathers stayed back here. No one can question my patriotism. *(Time-bell rings.)* Like my family, millions of Muslim families stayed back here. We have the same equal rights like any other in this country. Belittling us as foreigners or trying to evict us using CAA, NRC and countless other rules is not going to work. We, I along with all the Muslims, in this country are sons and daughters of this soil. No Government in power either in a State or in the Union can uproot us from our motherland. So stop playing your religious polarisation card.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI VIVEK K. TANKHA): Thank you, Mr. Abdulla.

SHRI M. MOHAMED ABDULLA: Let us collectively try to uplift this great nation for generations to come. With this, I conclude my speech. Thank you, Sir.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI VIVEK K. TANKHA): The next speaker is Mr. Sanjay Singh. Mr. Sanjay Singh, your time is 12 minutes.

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा - हमारे कुछ दोस्त, जो कभी इधर हुआ करते थे, अब वे उधर चले गए हैं, उनके लिए चंद पंक्तियों से अपनी बात शुरू करूंगा -

"कैसा ये हादसा है मेरी ज़िन्दगी के साथ।
मैं हूं किसी के साथ, मेरा दिल किसी के साथ।।"

4.00 **P.M.**

जो लोग उधर चले गए, उनका दिल हमारे साथ है, भले ही वे किसी के साथ हों। मान्यवर, इस बजट का बहुत ढोल पीटा जा रहा है कि बड़ा क्रांतिकारी, बड़ा अच्छा बजट, बड़ा विकसित भारत का बजट है। यह बजट क्या है? यह पूरे देश को पता चलना चाहिए कि भारत माता की रक्षा सेना के लिए जो बजट आता है, उस बजट में कटौती करने का काम किया गया। उसको 9.6 प्रतिशत से घटाकर 9.43 प्रतिशत किया गया। भारत का अन्नदाता किसान, जो अपने खून-पसीने से देश को चलाने का काम करता है, उसका बजट, कृषि का बजट 3.20 प्रतिशत से घटाकर 3.15 प्रतिशत किया गया। हिंदुस्तान 144 करोड़ लोगों का देश है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि स्वास्थ्य का बजट 1.97 प्रतिशत से घटाकर 1.85 प्रतिशत किया गया, ट्रांसपोर्ट का बजट 11.48 प्रतिशत से घटाकर 11.28 प्रतिशत किया गया। पेन्शन, जहां एक तरफ पुरानी पेन्शन की बहाली की मांग हो रही है, लाखों कर्मचारी सड़क पर हैं और मांग करते हैं कि पुरानी पेन्शन बहाल की जाए, इस सरकार ने पेन्शन का बजट 5.20 प्रतिशत से घटाकर 5.04 प्रतिशत करने का काम किया। एनर्जी का बजट 2.10 प्रतिशत से घटाकर 1.42 प्रतिशत करने का काम किया। वैज्ञानिक विभाग का बजट .7 प्रतिशत से घटाकर .6 प्रतिशत करने का काम किया। फूड सब्सिडी का बजट 4.38 प्रतिशत से घटाकर 4.25 प्रतिशत करने का काम किया। नॉर्थ-ईस्ट के विकास का बजट, मणिपुर की तो चर्चा आपने नहीं की, लेकिन नॉर्थ-ईस्ट के विकास का बजट आपने 0.13 प्रतिशत से घटाकर 0.12 प्रतिशत करने का काम किया। सामाजिक कल्याण, जिसमें आपका बिल्कुल यकीन नहीं है, उसका भी बजट आपने घटाया। आपने उसको 1.22 प्रतिशत से घटाकर 1.17 प्रतिशत करने का काम किया। आपने फर्टिलाइजर का, खाद का बजट 3.88 से

घटाकर 3.4 प्रतिशत करने का काम किया और फूड सब्सिडी घटाने का काम किया। यह है आपके विकसित भारत के खोखले बजट की सच्चाई। हर वर्ग को आपने चोट पहुंचाने का काम किया। आप कहते हैं कि आप दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। यह तो सच्चाई बताइए कि यह पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था किसके लिए हैं आप? आपने चंद पूंजीपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए, यह इस देश की सच्चाई है। आपने 16 लाख करोड़ रुपये पूंजीपतियों के माफ किए, देश के 14 प्रधान मंत्रियों ने जितना कर्जा लिया, उससे दुगुना कर्जा अकेले आपकी सरकार ने लिया।

(**सभापति महोदय** *पीठासीन हुए।*)

आपने डेढ़ सौ लाख करोड़ रुपये कर्जा लेने का काम किया, देश को कर्ज में डुबाने का काम किया। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि इस सरकार से किन-किन वर्गों को उम्मीद थी। इस सरकार से उम्मीद थी देश के अन्नदाता किसानों को कि आप एमएसपी दुगुना करेंगे। आपने एमएसपी दुगुनी नहीं की, आपने किसानों की फूड सब्सिडी काटने का काम किया, फर्टिलाइजर सब्सिडी काटने का काम किया, कृषि क्षेत्र को देने वाले बजट को खत्म करने का काम किया। बेरोजगारों को उम्मीद थी। आपने कहा था कि दस साल में 20 करोड़ नौकरियां देंगे। 20 करोड़ नौकरियां आपने नहीं दीं। फिर नौजवानों ने कहा कि नौकरी दो, नौकरी दो, फिर आपने कहा पकौड़ा तल लो, पकौड़ा तल लो, फिर आपने कहा कि पान की दुकान लगा लो, पान की दुकान लगा लो और फिर उसके बाद आपने कहा कि चार साल की नौकरी कर लो सेना में।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से भारत के प्रधान मंत्री से बड़ी विनम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं कि देश के प्रधान मंत्री को 73 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधान मंत्री बनना है, लेकिन किसान का बेटा, नौजवान सेना में चार साल की नौकरी करेगा, यह भेदभाव क्यों है, यह मैं पूछना चाहता हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, मैं इस सरकार से जानना चाहता हूं कि आपकी अगली योजना कौन सी आएगी? आप कह रहे हैं internship योजना, training योजना, पांच हजार रुपए की ट्रेनिंग ले लो। मान्यवर, क्या सरकार पांच हजार रुपए की ट्रेनिंग 500 बड़ी कम्पनियों में देगी? आप मुझे भारत की 100 कम्पनियां बता दीजिए, जिनमें से एक कम्पनी में आप चार हजार ट्रेनीज़ को रख सकते हैं, आप एक कम्पनी बता दीजिए, जिसमें आप चार हजार प्रशिक्षुओं को रख सकते हैं। यह भी आपका आंकड़ा सिर्फ एक जुमला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब मुझे लगता है कि एक ही योजना बाकी रह गई है। मान्यवर, वह योजना है कि हमारी भारत की सरकार, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार अगली योजना लेकर आएगी कि इस देश के नौजवानों को मुफ्त में पांच करोड़ कटोरा बांटा जाएगा, भीख मांगो योजना लाने का काम ये लोग करेंगे।

मान्यवर, आपने देश की अर्थव्यवस्था के बारे में कहा कि आप विश्व की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। इस पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था का लाभ किसको मिल रहा है, आपके चंद पूंजीपति

* को, जिनका 16 लाख करोड़ रुपया आपने माफ किया, जो हजारों करोड़ हिन्दुस्तान से लूटकर चले गए। मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं।

MR. CHAIRMAN: *word is deleted. ...*(Interruptions)*... Mr. Sanjay, * word is deleted. You will have difficulty. ...*(Interruptions)*...

श्री संजय सिंह: सर, ठीक है। मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश की अर्थव्यवस्था में रेहड़ी-पटरी वालों का कोई योगदान नहीं है, जो 10 करोड़ रेहड़ी-पटरी वाले पूरे देश में हैं, क्या उनका कोई योगदान नहीं है? वे भी सरकार को टैक्स भरते हैं। आपकी सरकार उनको फूंटी आंख से भी देखना नहीं चाहती है। आप ने रेहड़ी-पटरी वालों को कहा कि अपने नाम के आगे नेमप्लेट लगाओ, अपने नाम के आगे नेमप्लेट लगाओ। आप हिन्दू हो कि मुसलमान हो, दलित हो कि पिछड़े, आदिवासी हो या क्या हो, यह बताओ। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर नेमप्लेट लगवानी है,*...(**व्यवधान**)... मान्यवर, लगवाइए नेमप्लेट उन पूंजीपतियों को, जिन्होंने हिन्दुस्तान के बैंकों को खाली करने का काम किया है। मान्यवर, ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: One minute. ...*(Interruptions)*... Hon. Member, Sanjay*ji* you are a senior person. धारा प्रवाह में आप फिगर्स के बारे में काफी कुछ कह गए, बाकी तो, you can make your point, there is no difficulty about it. ...*(Interruptions)*... One minute. The figures which you have given, you will have tough time in proving them because these have been taken in stride. So, all that will be deleted. Hence, unless you have real factually firmed up material, use it. Otherwise, make your point. So, that point would be deleted. Make your point, there is no issue.

श्री संजय सिंह: सर, ठीक है। धन्यवाद सर। मान्यवर, मैं तो आपके माध्यम से यह कहना चाह रहा था कि इस तरह के काम देश के अंदर नहीं होने चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हम जानते हैं कि हमारी सामाजिक व्यवस्था कैसी है, लेकिन मैं जानता हूं कि इनके मन में दर्द होगा। अभी ये उत्तर प्रदेश में चुनाव हारे हैं। वहां पर अगर कोई बोर्ड लगाएगा जाटव ढाबा ...(**व्यवधान**)... एक सेकंड, अगर कोई जाटव ढाबा का बोर्ड लगाएगा, अगर कोई अपने ढाबे के आगे बाल्मीकि ढाबा लिखेगा, तो आप लोग उसके यहां पर खाने के लिए नहीं जाओगे। ...(**व्यवधान**)... मैं आपकी मानसिकता को जानता हूं। आप वे लोग हैं, जिन्होंने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को प्रभु श्री राम के मंदिर शिलान्यास में नहीं बुलाया, आप वे लोग हैं, जिन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया। ...(व्यवधान)... आप दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों से, मुसलमानों से नफरत करने का काम

* Expunged as ordered by the Chair.

करते हैं। यह आपकी सच्चाई है। इसलिए नेमप्लेट मत लगवाइए। नेमप्लेट लगवानी है, तो जिन्होंने देश के बैंकों को लूटा है, उनकी नेमप्लेट लगवाइए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से कहना चाहता हूं कि इन्होंने जेलों को भी कम बजट दिया है। जेल का बजट तो बढ़ा दीजिए। जेल का बजट 300 करोड़ है, जेल का बजट तो बढ़ा दीजिए। अभी हमें जेल में भेजा है, कल तुमको जेल में आना है, तुम सबको जेल में आना है, जेल का बजट बढ़ा दो, जेलों को ठीक कर दो, अगला नंबर तुम्हारा है। ..(**व्यवधान**)...तुम्हें जेल में आना है, इसलिए कम से कम जेलों को तो ठीक कर दो, अगला नंबर तुम्हारा है।..(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः संजय सिंह जी, एक मिनट।..(**व्यवधान**)... Mr. Sanjay Singh. *...(Interruptions)...* Mr. Sanjay Singh. *...(Interruptions)...*

श्री संजय सिंह : महोदय, मैं जेल के बजट पर बोल रहा हूं। ..(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: One second. *...(Interruptions)...* One second. *...(Interruptions)...*

श्री संजय सिंह : मान्यवर, मैं जेल के बजट पर बोल रहा हूं कि 300 करोड़ दिए हैं। मान्यवर, इन लोगों को जेल में आना है। ..(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: One second. *...(Interruptions)...* मैं सदन के नेता से जेल का बजट बढ़ाने के लिए अनुरोध करूंगा, क्योंकि यह बहुत मार्मिक अपील है।

श्री संजय सिंहः मान्यवर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : आप इस पर गौर फरमाइए।

श्री संजय सिंह : सर, आपका धन्यवाद।

श्री सभापति : ठीक है? इसकी एक पृष्ठभूमि भी है।

सभा के नेता (श्री जगत प्रकाश नड्डा) : सभापति महोदय, इसका ध्यान रखा जाएगा।

श्री संजय सिंह : मान्यवर, इन्होंने न्यायपालिकाओं के लिए जो बजट रखा है, वह नाकाफी है। इस देश के अंदर 5 करोड़ केस पेंडिंग हैं और 6 लाख लोगों को पूरे देश में जेलों में रखा गया है, जिनमें से करीब-करीब 76 प्रतिशत अंडर ट्रायल हैं। इसका मतलब यह है कि आपका मकसद न्याय दिलाना नहीं है, आपका मकसद किसी मामले की सच्चाई तक पहुँचना नहीं है, आपका

मकसद एक-एक व्यक्ति को पकड़-पकड़कर जेल में डालना है। आपने दिल्ली के मुख्य मंत्री को, जिनकी शुगर 36 बार 50 से नीचे जा चुकी है, उन मुख्य मंत्री को पकड़कर जेल में डाल दिया है।

श्री सभापति : एक मिनट रुकिए। ..(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंहः नहीं मान्यवर, आप इनको बार-बार मौका मत दीजिए। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। ..(**व्यवधान**)...

श्रम और रोजगार मंत्री ;तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (डा. मनसुख मांडविया) : सभापति महोदय..(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: After him. *...(Interruptions)...* After him. *...(Interruptions)...*

SHRI SANJAY SINGH: I am not yielding. *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: After him. *...(Interruptions)...* One minute only. *...(Interruptions)...*

श्री संजय सिंहः इन्होंने हैट्रिक बना ली है। ..(**व्यवधान**)...इन्होंने दिल्ली के मुख्य मंत्री को पकड़कर जेल में डालकर रखा है, दिल्ली के शिक्षा मंत्री को दो साल से जेल में रखा है, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को दो साल से जेल में रखा है। आप विपक्ष के एक-एक नेता को पकड़-पकड़कर जेल में डालते हैं। आपने मुख्य मंत्री हेमंत सोरेन को जेल में रखा, संजय रावत को जेल में रखा, अनिल देशमुख को जेल में रखा, आप सभी को पकड़-पकड़ कर जेल में रखते हैं। आपने बंगाल के तीन मंत्रियों को पकड़कर जेल में रखा। आपका मकसद ट्रायल कराना नहीं, न्याय दिलाना नहीं है, बल्कि आपका मकसद हम लोगों को पकड़कर जेल में रखना है। ..(**समय की घंटी**)..मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितना जेल में डालोगे, उतना गर्त में जाओगे। जिसने भी यह राजनीति की है, उसका समापन हो गया है। अभी 240 पर पहुंचे हो, कल 24 पर पहुँचोगे, इसके बाद 2 पर भी आओगे।..(**समय की घंटी**)..महोदय, मैं बस एक-दो बातें कहकर अपनी बात खत्म करूंगा, आप इसको मेरे टाइम में से काट लीजिएगा।

महोदय, भेदभाव की भी एक बात है। इनको सबसे भेदभाव करना है। मुसलमानों से भेदभाव, सिखों से भेदभाव, ईसाइयों से भेदभाव, दलितों से भेदभाव, पिछड़ों से भेदभाव, महिलाओं से भेदभाव और अब राज्यों से भेदभाव। सर, इन्होंने क्या भेदभाव किया है? 2 लाख, 32 हज़ार करोड़ रुपये दिल्ली के लोगों ने सरकार के केंद्रीय खजाने में जीएसटी और इनकम टैक्स के रूप में दिए, लेकिन बदले में हमें कितना मिलता है? यह संख्या जीरो है। नौ साल से आप दिल्ली को बजट नहीं दे रहे हैं। ..(**समय की घंटी**).... पंजाब के लोग...(**व्यवधान**)... सर, आप हमारी पार्टी के टाइम में से एक-दो मिनट काट लीजिएगा।

सर, मैं पंजाब के लिए कहना चाहता हूं। पंजाब का किसान अपना खून, पसीना बहाकर, खेत में गेहूँ पैदा करता है, धान पैदा करता है, लेकिन आपने पंजाब के विकास का 8 हज़ार करोड़ रुपया रोक रखा है, आपने विपक्ष के राज्यों का पैसा रोक रखा है। आप यह भेदभाव क्यों कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप लिखते हैं - राज्यों के विकास से देश का विकास है, क्या आप यह राज्यों का विकास कर रहे हैं? आपने एक-एक को टारगेट करके विपक्षी राज्यों के साथ भेदभाव करने का काम किया है।

महोदय, मैं अंत में कहूंगा कि कोई मुझसे कह रहा था कि सारे बजट कम किए हैं, आपने शिक्षा के बजट को भी कम कर दिया है। मैंने इन लोगों से कहा कि शिक्षा से इन लोगों का कोई लेना-देना नहीं है। मान्यवर, इनका शिक्षा से क्यों लेना-देना नहीं है? इनका शिक्षा से इसलिए कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि ये लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में मनुस्मृति पढ़ाने जा रहे हैं। ..(**समय की घंटी**).... ये लोग मनुस्मृति पढ़ाएंगे कि दलितों के, पिछड़ों के, जिनको आप शूद्र कहते हैं, अगर वे श्लोक सुन लेंगे, तो आप उनके कान में पारा कैसे डालेंगे? आप यह पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय में कराने जा रहे हैं। ..(**समय की घंटी**)....

MR. CHAIRMAN: Thank you. ...*(Interruptions)*... Thank you. ...*(Interruptions)*...

श्री संजय सिंह: इसलिए मान्यवर, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि यह बजट हिंदुस्तान के किसान के खिलाफ है, हिंदुस्तान के नौजवान के खिलाफ है, हिंदुस्तान के व्यापारियों के खिलाफ है,*

MR. CHAIRMAN: The latter part will not go on record. Hon. Members, I am privileged and honoured to be the Chancellor of Delhi University. The hon. Member has made some reflections. They are far distanced from reality. As the Chancellor of Delhi University, I am updating myself every fortnight, and this University is rising in excellence. Therefore, the observations of the hon. Member, perhaps, he needs to check up. ...*(Interruptions)*... If you check up, you will get clarified. Secondly...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): He will authenticate. ...*(Interruptions)*...

श्री सभापति: नहीं, नहीं। ...(**व्यवधान**)... सुनिए, सुनिए। ...(**व्यवधान**)... Sanjay, you are not on issue now. Jairam is trying to ridicule, make it a farcical situation for Chairman's well-meaning observation that in this House, we must use information which a Member must be prepared to authenticate. Now it is his mindset. In spite of his long career and ministerial background, that a Member should be so engaging, I

* Not recorded.

can only say, I have no words to reflect on this. I can only appeal to senior Members of the House that there is need for him to think within. ...*(Interruptions)*... One minute.

OBSERVATIONS BY THE CHAIR

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I need to put on record one thing which is relevant. In this country, governed by rule of law, the arrest may be by an agency, by the police, but sending someone to jail is not the police's job. ...*(Interruptions)*.... It is not the job of an agency also. A court, lawfully acting, sends a person to jail. So anyone, ...*(Interruptions)*... Please listen to me. Anyone in this country holding whatever position, of a minister or a Chief Minister otherwise, if he is in jail, it is in compliance of a Remand Order given by a Judicial Magistrate and, therefore, the assertion by the hon. Member that Executive is sending people to jail is not only factually wrong, but legally also not sustainable, and ...*(Interruptions)*...

GENERAL DISCUSSION ON

The Union Budget 2024-25
and
The Budget of Union Territory of Jammu & Kashmir 2024-25 - *Contd.*

श्री संजय सिंहः सर, जवाब तो सुन लीजिए। ...(**व्यवधान**)... सर, सर... ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः संजय जी, एक सेकंड। मैं आपको बोलने दूँगा। एक सेकंड। आप तो अनुभवी हैं। आप जब जेल गए, तब शुरू के अंदर तो एजेंसी का रोल था। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंहः सर, मैं वही बता रहा हूँ।

श्री सभापतिः उसके बाद ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के रिमांड से ही गए न?

श्री संजय सिंहः सर, मैं बता रहा हूँ।